https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'भाजपा ने एक संवेदनशील, पारदर्शी और निर्णायक सरकार देने का काम किया है'

वर्ष-12, अंक-11, 01-15 जून, 2017 (पाक्षिक) ₹20

साथ है, विश्वास है ..हो रहा विकास है

विदेश में धाक तो देश में साख

मोदी की आर्थिक नीतियां अधिक सुदृढ़: नये भारत की प्रेरणा

सुधारों के सिलसिले ने बदली तस्वीर

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लक्षद्वीप और चंडीगढ़ प्रवास की झलकियां

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **भाजपा ने एक संवेदनशील, पारदर्शी और निर्णायक सरकार देने का काम किया है: अमित शाह**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 मई को भाजपा के केन्द्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के तीन बेमिसाल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस...

वैचारिकी

जनसंघ के कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाएं 10

श्रद्धांजलि

अनिल माधव दवे नहीं रहे 11

लेख

विदेश में धाक तो देश में साख 19

मोदी की आर्थिक नीतियां अधिक सुदृढ़: नये भारत की प्रेरणा 22

"देव, दवे को अभी नहीं बुलाना था" 24

सुधारों के सिलसिले ने बदली तस्वीर 26

अन्य

'मोदीजी के नेतृत्व में देश में एक विकास यात्रा की शुरुआत हुई है' 15

'आंध्र प्रदेश को भाजपा का मजबूत गढ़ बनायेंगे' 17

निराशा से नई आशा की ओर: एम. वेंकैया नायडू 27

सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए: नरेंद्र मोदी 28

2013-2014 की तुलना में 2016-2017 में 5 गुना... 32

ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल का शुभारंभ 33

संगठनात्मक गतिविधियां

12 **'लक्षद्वीप के रिहायशी द्वीपों में ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा'**
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर श्री अमित शाह 16 मई को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की...

13 **'यह समय आराम करने का नहीं, काम करने का है'**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 मई को चंडीगढ़ में पार्टी...

सरकार की उपलब्धियां

29 **ढोला-सदिया : पूर्वोत्तर के लिए नई आशा का पुल**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को असम में देश के सबसे लम्बे नदी पुल...

30 **किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में तीन वर्ष में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

देश हर कदम पर हमारे साथ चला, हर परिस्थिति में साथ चला। 125 करोड़ लोगों ने विश्वास को और मजबूत बनाया।

@rajnathsingh

पूर्वोत्तर की वास्तविक क्षमता को सामने लाने के लिए हम संकल्पित हैं। इस क्षेत्र की अपनी क्षमता प्राप्त करने में शांति और सुरक्षा मदद करेगी।

@arunjaitley

भारतीय सेना द्वारा सीमा पार की कार्रवाई का सरकार समर्थन करती है। जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्यवाइयों की जरूरत है।

@PrakashJavdekar

हर नियुक्ति मेरिट पर हुई है और होगी। हम किसी का रंग देखकर नियुक्ति नहीं करते।

facebook

विकास उन्मुख मोदी सरकार ने विकास को देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचा कर सच्चे अर्थों में अंत्योदय की कल्पना को चरितार्थ किया है। गत 3 वर्षों में मोदी जी ने देश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त कर राजनीति की दिशा बदलने का अभूतपूर्व कार्य किया है।

— अमित शाह

राज्य में कुम्हारों और माटी शिल्पकारों की आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने हेतु सरकार ने 'झारखण्ड माटी कला बोर्ड' का गठन किया है। झारखण्ड सरकार पूरी तरह यह प्रयास करेगी कि उनको तकनीकी सहायता भी प्राप्त हो।

— रघुबर दास

बस्तर में स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाओं का विकास राज्य सरकार की एक बड़ी सफलता है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल और डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की सेवा भावना बस्तर को स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से स्वावलंबी बना रही है।

— डॉ. रमन सिंह

व्यंग्य चित्र

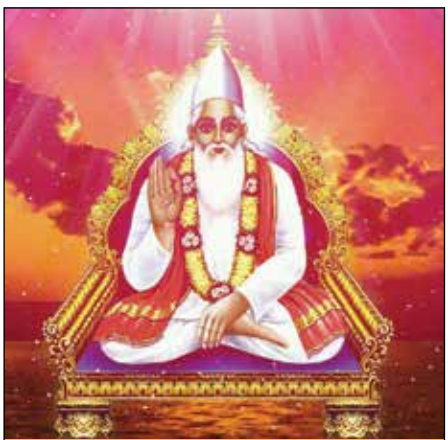

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
संत कबीर जयंती
की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

अपने देश में अनेकता में एकता की बात सर्वोपरि रही है। भारत एक जन है और यह बात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो हजारों वर्षों से, परम्परा से देश का व्यवहार रहा है। आज तो किसी से संपर्क करना बहुत आसान है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पैदल–पैदल जाना होता था। तब भी देश के चारों कोनों में चार पीठ स्थापित हुए। बद्री, केदार से कन्याकुमारी जाओ, यात्रा करो, मिलो–जुलो, यह सारी एकता की भावना भरी थी लोगों में।

-कुशाभाऊ ठाकरे

चमत्कारी परिवर्तन के तीन वर्ष

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो गये। इन तीन वर्षों में लोग भरपूर आत्मविश्वास से ओत–प्रोत होकर पूरे विश्व में भारत के बढ़ते कद का साक्षात्कार कर रहे हैं। गांव, गरीब और किसान को समर्पित यह सरकार लड़खड़ाती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक योजनाओं एवं प्रकल्पों से जान फूंकने के लिए जानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा नोटबंदी के साहसिक निर्णय से काले धन एवं हवाला पर कड़ा प्रहार हुआ है। देश एक भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसकी उपलब्धियों की धाक पूरे विश्व में मानी जा रही है। अभी केवल तीन वर्ष पहले की बात है जब कई विशेषज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर प्रश्न चिह्न खड़े कर रहे थे, आज यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत अंधकारमय वैश्विक परिदृश्य में एक चमकता हुआ सितारा के रूप में उभरा है। तीन वर्ष पूर्व जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस समय की तुलना यदि आज से कोई करे तो शायद ही विश्वास कर पाएगा कि इतने कम समय में कोई देश इतनी तेजी से पुनः उठ खड़ा हो सकता है और एक लंबी छलांग लगाने को स्वयं को तैयार कर सकता है। अविश्वसनीय तो है परन्तु आज की सच्चाई यही है।

इतने कम समय में भयंकर पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टाचार एवं कुशासन के दौर से भारत कैसे निकल गया? हाशिए से उठकर आज भारत वैश्विक रंगमंच पर एक प्रमुख भूमिका कैसे निभा रहा है? भारत आज निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा देश कैसे बना? ऐसा कैसे हुआ कि तीन वर्षों में किसी भी मंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप तक नहीं लगे? कैसे भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर 'सर्जिकल स्ट्राइक' किया तथा आतंकवादियों के कई पाकिस्तानी पनाहगारों को बमबारी से ध्वस्त कर दिया? इतने व्यापक स्तर पर नोटबंदी और उसको इतना ही भारी जनसमर्थन– कैसे संभव हुआ? इस तरह के ना जाने कई प्रश्न कइयों के मन–मस्तिष्क में उमड़–घुमड़ रहे हैं। जिस तरह से भारत की तस्वीर का कायाकल्प हुआ है किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिरकार यह कैसे संभव हुआ? आज जबकि पूरा विश्व अचंभे से भरा इस परिवर्तन को देख रहा है, नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जिस प्रकार की दृष्टि, राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा प्रतिबद्धता आज नेतृत्व में दिख रही है अभी मात्र कुछ वर्षों पहले तक यह अकल्पनीय था। अनेक प्रकार की अभिनव योजना, इनका लाभ तथा जिस तेजी से इनका क्रियान्वयन हो रहा है उससे पूरे देश का विश्वास नेतृत्व पर गहरा हुआ है। 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ भारत बहुत तेजी से विकास के रास्ते चल पड़ा है जिसमें जन–जन को भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। नरेन्द्र मोदी के प्रति भारी विश्वास, उनके नेतृत्व पर आस्था तथा उनसे जन–जन की जुड़ी आकांक्षा एवं अपेक्षाएं चुनाव दर चुनाव में परिलक्षित हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नया भारत' का उद्घोष का आधार 'परफॉर्मेंस की राजनीति' बन रही है जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। जातिवाद, तुष्टिकरण एवं वंशवाद की राजनीति की लगातार हार से एक व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश की जनता अब 'परफॉर्मेंस' के आधार पर वोट देना अधिक पसंद कर रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दिव्यांग, दलित, जनजाति तथा पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नया भारत' का उद्घोष का आधार 'परफॉर्मेंस की राजनीति' बन रही है जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। जातिवाद, तुष्टिकरण एवं वंशवाद की राजनीति की लगातार हार से एक व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश की जनता अब 'परफॉर्मेंस' के आधार पर वोट देना अधिक पसंद कर रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दिव्यांग, दलित, जनजाति तथा पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। गांवों एवं कृषि पर जोर तथा गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाओं से अर्थव्यवस्था की अब तक की आंतरिक असंतुलन को तेजी से सुधारा जा रहा है। अनगिनत अभिनव योजनाओं एवं प्रकल्पों के माध्यम से देश में समग्र विकास की नींव रखी जा रही है। अनेक वैश्विक मानदण्डों पर भारत ने अब अपनी स्थिति को तेजी से सुधारा है और अब पूरा विश्व भारत को आदर और अपेक्षा के साथ देख रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में बड़े कदम बढ़ाये हैं और व्यापक परिवर्तन हो रहा है। यह वास्तव में चमत्कारी परिवर्तन है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भाजपा ने एक संवेदनशील, पारदर्शी और निर्णायक सरकार देने का काम किया है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 मई को भाजपा के केन्द्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में केंद्र की भाजपा सरकार के तीन बेमिसाल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों और गरीब-कल्याण की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की।

साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन तीन वर्षों में कई क्षेत्रों में असाधारण काम करके मील का पत्थर स्थापित किया है और एक महान भारत की नींव डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन तीन सालों में देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाने, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा व मान-सम्मान में वृद्धि करने और देश की सोच के स्केल को बदलने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में देश की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है, इन तीन वर्षों में हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में देश की राजनीति में से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण के अभिशाप को ख़त्म करने का काम हुआ है, जो देश की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में जो चीजें हम अचीव नहीं कर पाए, मोदी सरकार ने इन तीन वर्षों में उन चीजों को हासिल करने में सफलता अर्जित की है और इसलिए हमने भाजपा सरकार के तीन साल के पूरे होने पर लोकसंपर्क अभियान का नारा बनाया है - साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की 1955 से लंबित मांग को पूरा कर के देश के करोड़ों पिछड़े लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि 40 सालों से लंबित पूर्व सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) को पूरा करके संवेदनशील भाजपा सरकार ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की राशि को पूर्व सैनिकों के खाते में सीधा

पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया में उभरा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस राजनीतिक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया, उससे भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक राष्ट्रवादी सरकार का परिचय देते हुए शत्रु संपत्ति बिल को क़ानून बनाकर इसपर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी, फर्जी कंपनियों के खिलाफ एक्शन और बेनामी संपत्ति का क़ानून लाकर मोदी सरकार ने काले-धन को ख़त्म करने की दिशा में निर्णायक पहल की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव सुधार की एक नई सोच देश की जनता और सभी राजनीतिक दलों के सामने रखने का काम किया, ताकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव एक ही दिन कराया जा सके और जनता के ऊपर से चुनाव खर्च के बोझ को कम किया जा सके।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी दलों को साथ लाकर जीएसटी के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' के स्वप्न को साकार करके दिखाया है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ग्यारह सौ से ज्यादा अप्रासंगिक कानूनों को ख़त्म करके मोदी सरकार ने क़ानून के जंगल में मंगल का काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपया आवंटित करके गरीबों की जिन्दगी को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम एप शुरू करके गरीबों को डिजिटल ट्रांजेक्शन का सबसे पॉपुलर एप उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि विकलांगों को दिव्यांग का नाम देकर और उनकी भलाई के लिए कई योजनायें लाकर मोदी सरकार ने एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि मैटरनिटी की छुट्टी को 26 सप्ताह तक बढ़ा कर मोदी जी ने इस देश के करोड़ों गर्भवती महिलाओं को खुद के और बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल करने का मौक़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक निर्णायक सरकार है, त्वरित फैसले लेने वाली सरकार है और योजनाओं को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में हमने देश को पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार के स्थान पर एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए भी मोदी सरकार ने काफी कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हलके लड़ाकू विमान 'तेजस' को वायु सेना में सम्मिलित करके 'मेक इन इंडिया' इनिशिएटिव को बहुत बड़ा बल प्रदान किया गया है। साथ ही, सेना के आधुनिकीकरण को भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया ने सराहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में भी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि लाल बत्ती के वीआईपी कल्चर को बदलने का काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन-समस्याओं को जन-भागीदारी से सुलझाने की पहल भी मोदी सरकार ने की है।

उपलब्धियों भरा वर्ष

श्री शाह ने कहा कि मैं यह गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पिछला वित्तीय वर्ष कई मायनों में बेमिसाल उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। उन्होंने कहा कि 2016-17 वित्तीय वर्ष में यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किये गए, सबसे ज्यादा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी दलों को साथ लाकर जीएसटी के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' के स्वप्न को साकार करके दिखाया है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ग्यारह सौ से ज्यादा अप्रासंगिक कानूनों को ख़त्म करके मोदी सरकार ने क़ानून के जंगल में मंगल का काम किया है।

कोयले का उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा विद्युत् उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे के विकास के लिए दी गई, सबसे ज्यादा राजमार्ग बनाए गए, सबसे ज्यादा तेज गति से ग्रामीण सड़कें बनाई गयी, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया और सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी व टू व्हीलर का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है, यही बताता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया की नींव रखने

का काम किया है। वे देश को महान भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर बढ़े हैं।

सोशल सेक्टर में सुधार

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग साढ़े 28 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा के अंतर्गत लगभग 13 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के दो करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, गिव इट अप के तहत लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, जेनेरिक दवाओं के माध्यम से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, स्टैंट के दाम 80% तक कम किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित देश के 18 हजार गांवों में से लगभग 13 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, बाकी बचे गांवों

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा के अंतर्गत लगभग 13 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के दो करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, गिव इट अप के तहत लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है।

में भी 2018 तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से साढ़े साथ करोड़ युवाओं को स्वरोजगार के लिए काफी आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2018 तक लेप्रोसी और कालाजार से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, 2020 तक चेचक से मुक्ति पाने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश भर में लगभग साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है, मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से साढ़े सात करोड़ बच्चों के टीकाकरण का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं के स्किल अपग्रेडेशन का कार्य तेज गति से प्रगति पर है। स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से देश भर में लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में 42% की वृद्धि हुई है, यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट के माध्यम से मजदूरों की बहुत सारी समस्याओं का अंत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक गरीब और बूढ़े मजदूरों के पेंशन को न्यूनतम एक हजार करके सम्मान देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ग तीन और वर्ग चार की नौकरी में से इंटरव्यू को ख़त्म करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है, भाजपा की सभी राज्य सरकारों ने भी इस पारदर्शी मॉडल को अपनाया है।

भारत: दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। महंगाई काबू में है, विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, सेंसेक्स 31000 को पार कर गई है और निफ्टी भी अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। उन्होंने कहा कि बिजली उपलब्धता में भारत 2014 में दुनिया में 99वें स्थान पर था, जबकि आज हम 76 स्थान ऊपर उठ कर 26वें स्थान पर आ गए हैं जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास दर पांच प्रतिशत से ऊपर रहा है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के अनुसार भारत का विकास दर 7.2 फीसदी रहने की संभावना है, जबकि कांग्रेस की यूपीए सरकार 2014 में इसे 4.8 फीसद में छोड़ कर गई थी। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष कृषि विकास दर में वृद्धि दर्ज की गई है, कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय कृषि विकास दर ऋणात्मक थी, जबकि मोदी सरकार में यह लगातार 4% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 71वें स्थान से 39वें स्थान पर आ गाये हैं। उन्होंने कहा कि नेमुरा के अनुसार, निर्यात में शुरुआती गिरावट के बात लगातार वृद्धि का दौर जारी है और मार्च महीने में यह सालाना आधार पर 27.6 प्रतिशत बढ़ा है। एफडीआई में 45% की वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट में तेजी आई है, ब्याज दरों में कटौती करने में हमें सफलता मिली है, राजकोषीय खाते को 3.9 प्रतिशत तक रखने में हम सफल हुए हैं और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है जो आजादी के बाद से सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष जहां भारत में प्रति व्यक्ति आय 93,293 रुपये थी, वहीं इस वित्त वर्ष यह 103,007 रुपये रहने का अनुमान है।

काले धन पर प्रहार

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व

में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तीन वर्षों में काले-धन के रास्ते को बंद करने के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए काले-धन के खिलाफ लड़ाई की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। फर्जी कंपनियों के खिलाफ एक्शन और बेनामी संपत्ति का क़ानून लाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार ने काले-धन को रोकने की दिशा में निर्णायक पहल की। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित की गई और इससे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्डरिंग के जरिये अर्जित की गई बेनामी संपत्ति में से लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति सीज की गई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई की कटिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि लगभग 9.36 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई है, साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशस रूट बंद करके काले धन को वापिस लाने को अर्थतंत्र में वापस लाने के रास्ते बंद किये गए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए और चुनावी राजनीति में से काले-धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए कैश में लिए जाने वाले चंदे की रकम को दो हजार रुपये तक सीमित करने का साहस भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार

श्री शाह ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ई-मंडी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से खेत से लेकर खलिहान तक किसानों की फसल को सुरक्षित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि रबी और खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार वृद्धि की गई है, दलहन फसलों को एमएसपी पर खरीद कर सरकार ने दाल उत्पादक किसानों को काफी राहत प्रदान की गयी है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों की सुविधा में बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय किसानों को सहायता देने के सभी पैमानों में बढ़ोत्तरी की गई है। किसानों को दी जाने वाली आवंटित राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया है, गन्ना किसानों का भुगतान लगभग-लगभग पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया के मदद से पेस्टीसाइड के उपयोग और खाद के उपयोग में कमी लाई गई है, साथ ही खादों के दाम में भी आजादी के बाद पहली बार कमी आई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज प्रगति

श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद सबसे तेज गति से राजमार्गों का निर्माण मोदी सरकार में हो रहा है, राजमार्गों को लेवी फ्री एवं क्रोसिंग फ्री बनाने का काम किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी सड़क पुल भूपेन हजारिक का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि विद्युत् उत्पादन क्षमता में एक तिहाई जबकि विद्युत् ट्रांसमिशन में एक चौथाई बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लगभग 30 करोड़ एलइडी बल्ब बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 28 लाख विदेशी पर्यटकों को देश में लाने का काम किया गया है, इसमें लगभग 13% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम सड़क योजना में लगभग 130

2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद देश में हुए सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है और ज्यादातर चुनावों में विजय प्राप्त की है, यह मोदी सरकार को जनता का सर्टिफिकेट है।

किलोमीटर सड़क रोज बनाया गया है, उड़ान के माध्यम से सस्ती हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है, सागरमाला में कार्य प्रगति पर है और नाविक नेविगेशन में भी दुनिया के कई देश भारत के साथ आ रहे हैं, होम लोन की दर को कम करके लोगों को राहत दी गयी है और सस्ते घर के सपने को साकार करने का काम हुआ है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का सबसे बड़ा पैमाना जनता का जनादेश होता है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद देश में हुए सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है और ज्यादातर चुनावों में विजय प्राप्त की है, यह मोदी सरकार को जनता का सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा कि देश की जनता यह मानती है कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, देश के गौरव को बढ़ाने वाली सरकार है, पारदर्शी व निर्णायक सरकार है। उन्होंने कहा कि देश की जनता मानती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आजादी के बाद से देश के सबसे लोकप्रिय लोकनेता बन कर उभरे हैं। ■

जनसंघ के कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाएं

प्रथम महानिर्वाचन के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्रदेश महामंत्री के नाते पं. दीनदयाल का पत्र

यह आवश्यक है कि हम अपने क्षेत्र की जनता से पिछले दिनों में स्थापित संपर्क को पानी की रेखा के समान मिटने न दें, बल्कि दृढ़तर करते रहें। कांग्रेस शासन का पिछला ढर्रा तथा आज भी जैसे लोग तथा जिस प्रकार विधानसभाओं में पहुंचे हैं, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि जनता के कष्ट अगले पांच वर्षों में कम न होकर बढ़ेंगे ही। विभिन्न क्षेत्रों में अन्याय और अत्याचारों की परंपरा टूटने वाली नहीं, हमें समाज के ऊपर आने वाली आपत्ति में, वह एक व्यक्ति पर हो या समुदाय पर हो, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें आप सदा आगे रहेंगे, यही विश्वास है। चुनावों में भारतीय जनसंघ की स्थिति, उसके परिणाम एवं आगे की अपनी गतिविधि यह पिछले दिनों में आम चर्चा का विषय रहा है। इस संबंध में प्रांतीय और अखिल भारतीय स्तर पर भी विचार हुआ है। सभी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यद्यपि चुनावों के परिणाम 'सीट्स' जीतने की दृष्टि से, जिसके लिए हमारी कमियों के अतिरिक्त कांग्रेस सरकार की अनियमितताएं भी बहुत कुछ जिम्मेदार हैं, संतोषजनक नहीं कहे जा सकते किंतु समाज में प्रवेश, प्रचार, अनुभव एवं वास्तविक जनतंत्र के लिए आवश्यक सही विरोधी दल के निर्माण कार्य में हमें पर्याप्त सफलता मिली है। चुनावों में हमारी ताकत और कमजोरी, हमारी अच्छाइयां और बुराईयां दोनों ही प्रकट हुई हैं। हां, संपूर्ण स्थिति का गहराई से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि भारत के राजनीतिक मंच पर भारतीय जनसंघ ऐसी शक्ति के रूप में आविर्भूत हो चुका है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु जनसाधारण के लिए समझने योग्य एवं दृश्यप्रभावी स्वरूप उपस्थित करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा।

चुनावों के अवसर पर काफी परिश्रम करके हमने अपने कार्य की नींव रखी है, यदि हम बराबर काम करते रहे तो मुझे विश्वास है कि हम अपने दल को सुदृढ़ रूप में खड़ा कर सकेंगे। भारतीय जनसंघ तो चुनावों के समय शैशवावस्था में था ही, हमारे बहुत से प्रत्याशी भी ऐसे थे जो सच्चरित्र, ईमानदार एवं योग्य होते हुए भी जनता के समक्ष जन नेता के रूप में पहली ही बार आए थे। अखिल भारतीय कार्यकारिणी ने यह अनुभव किया कि हमारी संस्था का ही नहीं अपितु हमारे उम्मीदवारों का भी जनजीवन में गहरा प्रवेश होना चाहिए। जब जनता अनुभव करेगी कि ये लोग वोट के लिए ही हमारे सामने नहीं आते, बल्कि हमारी कठिनाईयों में सदा साथ देते हैं तो हमें उनका प्रतिनिधित्व करते देर नहीं लगेगी।

केंद्रीय कार्यकारिणी ने जनसंघ को सुदृढ़ करने की दृष्टि से निम्न पंचविध कार्यक्रम की योजना की है-

1. जनसंघ की शाखाएं: ग्राम-ग्राम में खोलना तथा नए सदस्यों की भरती करना। आप जितने सदस्य बना लेंगे, उतना ही कार्य-विस्तार की दृष्टि से लाभ होगा।

2. निर्वाचन यंत्र का निर्माण: निर्वाचन की दृष्टि से अपने सभी कार्यकर्ताओं को योग्य ज्ञान से युक्त करना तथा प्रत्येक पद पर सतर्कता की वृत्ति पैदा करना।

3. रचनात्मक कार्यक्रम: राष्ट्र के विभिन्न प्रश्नों पर अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करते हुए उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करना तथा वहां आवश्यक संगठनों का निर्माण करना।

4. आंदोलनात्मक: शिकायतों का संगठित एवं वैधानिक रूप से व्यक्तिकरण (organised ventilation of grievances) आवश्यक। जनता की विभिन्न प्रकार की शिकायतें रहती हैं। वे उनको दूर करने का प्रयत्न नहीं करते, न उन्हें ज्ञान है कि कैसे किया जाए? केवल इधर-उधर चर्चा करते रहने से असंतोष, निराशा और विफलता का ही भाव पैदा होता है। शासन को भी कई बार उनका ठीक रूप से ज्ञान न होने के कारण, सरकार के द्वारा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सकता। अतः आवश्यक है कि सभी प्रकार की शिकायतों को जनसंघ की समितियां एवं कार्यकर्ता लें, उन्हें योग्य अधिकारियों तक ले जाएं और उनको दूर कराने का प्रयत्न करें। यदि आवश्यक हो तो जनमत तैयार करके उसका दबाव भी डाला जाए।

5. प्रचारात्मक: जनसंघ के विचारों, कार्यक्रमों एवं उसकी गतिविधि का प्रचार सभी साधनों से किया जाए। मैं समझता हूं कि उपर्युक्त आधार पर हम लोग यदि अपने कार्य को गति देंगे तो वह निश्चित रूप से वेग के साथ प्रसृत होगा। विधानसभाओं में संगठित एवं सशक्त विरोधी दल के अभाव को हमें बाहर से सही आधार पर विरोधी दल निर्माण करके पूरा करना होगा। यदि हमने बाहर जनमत अपने पीछे रखा तो उसको व्यक्त करने वाले जो थोड़े से हमारे सदस्य विधानसभा में हैं, उनका आवाज को भी बल मिलेगा। ये सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही नहीं, भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि हैं। जनता के कष्ट, वे फिर चाहे कहीं के हों, उनकी ओर विधानसभा का ध्यान खींचने का काम ये बराबर करते रहेंगे। हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है।

पत्र काफी लंबा हो गया है किंतु फिर भी अंत में यह लिखना आवश्यक समझता हूं कि काम में जुट जाने की जरूरत है। ऊपर से जो कुछ निश्चित हुआ है, वह ऊपर लिखा है और भी जो-जो निश्चित होगा, वह आपके पास पहुंचेगा किंतु वहां के संपूर्ण निश्चय अपने कार्य पर ही निर्भर हैं। साथ ही, पीछे क्या हुआ, इससे हम आगे क्या करते हैं, इसका ही अधिक महत्व है। उधर हम प्रवृत्त हों, यही अनुरोध है। विशेष कुछ हो तो सूचित कीजिएगा तथा प्रांतीय कार्यालय से संबंध बनाए रखिए। ■

- पांचजन्य, अप्रैल १०, १९५१

अनिल माधव दवे नहीं रहे

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे का 18 मई को 61 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। श्री दवे का 19 मई को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदी के संगम बांद्राभान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्री दवे के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉ. हर्षवर्धन, श्री अनंत कुमार, श्री कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़ी तादाद में भाजपा नेता मौजूद थे।

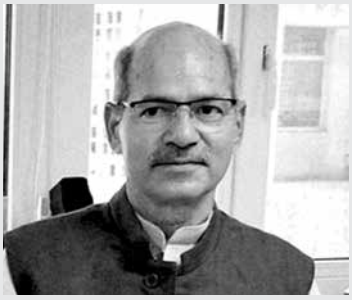

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, "मेरे मित्र और एक अत्यधिक सम्मानित सहयोगी पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं। अनिल माधव दवे जी को एक समर्पित लोक सेवक के तौर पर याद किया जाएगा। वह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी जुझारू थे। मैं कल शाम को अनिल दवे जी के साथ था, उनके साथ नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। उनका निधन मेरा निजी नुकसान है।"

जीवन परिचय

श्री अनिल माधव दवे का जन्म 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। इंदौर के गुजराती कॉलेज से एम. कॉम करने वाले श्री दवे शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे और नर्मदा नदी बचाओ अभियान में काम कर रहे थे। वह राज्य सभा में साल 2009 से मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जल संसाधन समिति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति में भी थे। ग्लोबल वार्मिंग पर संसदीय समिति के भी वह सदस्य रहे।

श्री दवे विद्वान, गैर पेशेवर पायलट, फोटोग्राफर और पढ़ने में रुचि रखने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शिवाजी के सुशासन पर शिवाजी और सूरज नामक पुस्तक लिखी। इसका प्राक्कथन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने मासिक पत्रिका चरैवेति तथा जन अभियान परिषद पत्रिका का संपादन किया। श्री दवे ने एक बार नर्मदा किनारे 18 घंटे तक विमान उड़ाकर अपनी परिक्रमा पूरी की। उन्होंने 19 दिनों में नर्मदा नदी में 1312 किलोमीटर नौका यात्रा की।

वे एक कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी एवं ईमानदार राजनेता एवं समाजसेवी थे। उन्होंने मानवता तथा राष्ट्र के लिए ऐसे अनेक उत्कृष्ट कार्यों को किया, जो भारतीय समाज के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। देश के प्राकृतिक संसाधनों, जो मानव जाति एवं अन्य प्राणियों की जीवनरेखा हैं, के प्रति उन्होंने अपार चिंता की। नर्मदा नदी की पूरी लंबाई की उन्होंने पैदल यात्रा की तथा तकनीक के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास किये। ■

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा जारी

शोक-संदेश

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संवेदनशील पर्यावरणविद एवं केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध और अत्यंत दुखी हूं। वे एक समर्पित जनसेवक, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता एवं उत्कृष्ट राजनेता थे।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री दवे लगातार दो बार मध्य प्रदेश से राज्य सभा के सांसद रहे। वे पिछले साल 5 जुलाई, 2016 को ही मोदी सरकार में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बने थे। वे ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर पार्लियामेंट्री फ़ोरम के भी सदस्य थे। इसके अतिरिक्त वे जल संसाधन समेत कई समितियों के भी सदस्य रहे। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए श्री दवे ने काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए कई किताबें भी लिखी हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनका योगदान काफी सराहनीय रहा है। सौम्य व्यक्तित्त्व, कुशल सांगठनिक क्षमता, ओजस्वी वक्ता और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में श्री दवे सदैव याद किये जायेंगें। उनके निधन से देश ने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता एवं कुशल मार्गदर्शक को खो दिया है। श्री दवे का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ■

'लक्षद्वीप के रिहायशी द्वीपों में ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर श्री अमित शाह 16 मई को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे। यहां उनका तीन दिवसीय प्रवास रहा। श्री शाह एंडरोथ द्वीप पर दो मछुआरों के घर गए। इन दो घरों में उन्होंने लगभग एक घंटे का समय बिताया और मछुआरों का हालचाल पूछा। उन्होंने मछुआरों से उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में पूछा। श्री शाह ने 42 साल के अब्दुल खादेर के घर पर नाश्ते में इडली और डोसा खाया। वह एक अन्य मछुआरे अब्दुल रहमान के घर भी गए। उन्होंने 76 साल की लोक गायिका पू (फूल) से भी मुलाकात की। गायिका वृद्धावस्था की बीमारियों के चलते बिस्तर पर हैं। श्री शाह ने गायिका की बेटी से उनकी सेहत के बारे में बात की। भाजपा अध्यक्ष से मिलने आए कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें द्वीप पर बेहतर शैक्षणिक एवं चिकित्सीय सुविधाएं चाहिए। इस दौरे का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश में पार्टी की मौजूदगी को प्रसार देना है। यहां लोकसभा की एक सीट है। अपनी चिकित्सीय एवं शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्षद्वीप कोच्चि पर निर्भर करता है। इस प्रदेश में दस बसे हुए और 17 निर्जन द्वीप हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में लक्षद्वीप की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कारावत्ती को केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया जाएगा और लक्षद्वीप के रिहायशी द्वीपों में ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि दो साल के भीतर सभी दस रिहायशी द्वीपों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिनमें अगाती, अमिनी, अंद्रोथ, बित्रा, कदामथ, कालपेनी, कारावत्ती, किल्तान, मिनिकाय और चेतलात शामिल हैं। श्री शाह ने यहां एक सभा में कहा, 'प्रधानमंत्री नवंबर के अंत में कारावत्ती द्वीप की यात्रा पर आएंगे और वे पूरा दिन यहां रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली लौटने के बाद लक्षद्वीप के दस द्वीपों के लिए एक परियोजना तैयार करेंगे। और यहां अधिक मालवाहक पोत, कोल्ड स्टोरेज तथा 4 जी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने यहां भाजपा लक्षद्वीप राज्य समिति के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। ■

@AmitShah

"तीन दिवसीय बूथ पर्व के लिए लक्षद्वीप पहुंच गया हूं... अलग प्रांत, अलग लोग, अलग संस्कृति लेकिन भाजपा के लिए एक जैसा उत्साह और समर्थन।''

'यह समय आराम करने का नहीं, काम करने का है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 मई को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशताब्दी के अवसर पर शुरू की गई पार्टी विस्तारक योजना का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करते हुए इकाई का गठन करना ही पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का पहला कर्तव्य होना चाहिए।

श्री शाह चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों, जिला अध्यक्षों, महासचिवों, मोर्चा अध्यक्षों एवं विभिन्न मोर्चों के महासचिवों, मंडल अध्यक्षों, सरपंचों तथा पंचायत प्रतिनिधियों, मार्केट कमेटी निदेशक, विस्तारक योजना के भागीदारों, प्रकल्प तथा विभाग समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चंडीगढ़ प्रभारी श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद श्रीमती सुधा यादव, चंडीगढ़ की सांसद श्रीमती किरण खेर, चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती आशा जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह इन दिनों पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए 95 दिनों की यात्रा पर प्रवासरत हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। कार्यकर्ताओं के बल भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ देश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वह एक बूथ पर कम से कम 15 सदस्य बनाने का फैसला करके विस्तारक के रूप में समय दें।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के विस्तारक को एक बूथ पर कम से एक दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में विस्तारक को कम से तीन दिन एक बूथ

पर व्यतीत करना चाहिए।

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा की स्थानीय इकाई को बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर चंडीगढ़ इकाई द्वारा एक पत्रिका निकाली जाए, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ स्थानीय सांसद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों तथा नगर निगम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह पत्रिका चंडीगढ़ के प्रत्येक घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए।

श्री शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वह पार्टी की विचारधारा के साथ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि यह समय आराम करने का नहीं बल्कि काम करने का है। उन्होंने पार्टी नेताओं को कहा कि वह अधिक से अधिक समय जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनें और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दें।

श्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार अब अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है। इस दौरान हमने राजनीति से जातिवाद, परिवाद और तुष्टीकरण की नीति को समाप्त किया है। हमारी पार्टी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनायी है और देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं।

मोदी सरकार अब अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है। इस दौरान हमने राजनीति से जातिवाद, परिवाद और तुष्टीकरण की नीति को समाप्त किया है। हमारी पार्टी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनायी है और देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हमने उत्तर पूर्व के राज्यों को भी विकास की ओर ले जाने के लिए आधारभूत संरचनाएं जुटानी शुरू कर दी है। हमने कालाधन के खिलाफ जंग छेड़ी है। जीएसटी जैसा कानून बनाना हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि है। मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं।

हमने उत्तर पूर्व के राज्यों को भी विकास की ओर ले जाने के लिए आधारभूत संरचनाएं जुटानी शुरू कर दी है। हमने कालाधन के खिलाफ जंग छेड़ी है। जीएसटी जैसा कानून बनाना हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि है। मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। श्री शाह ने कहा कि हमने जनादेश का पूरा सम्मान किया है। जनता ने हमें काम करने का जो मौका दिया है, हम उसके लिए आभारी हैं। इन तीन सालों में हमने जनता के बीच बहुत अच्छा संदेश भेजा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद भाजपा ने अब तक कुल 107 योजनाएं देश भर में लागू की हैं। इन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चंडीगढ़ प्रभारी श्री प्रभात झा ने कहा कि पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को सार्थक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी का पूरी तरह साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तमाम राजनीतिक दल देश में राजनीति की आड़ में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि केवल भाजपा ही लोकतांत्रिक मूल्यों को निर्वहन कर जनहित के फैसले ले रही है।

इससे पहले चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष श्री संजय टंडन ने श्री अमित शाह का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे ने चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं में जोश भरा था और पार्टी चुनाव जीती थी। ठीक उसी तरह से आज का यह दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा और पार्टी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान और विस्तारक योजनाओं को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाएंगे।

इससे पहले चंडीगढ़ पहुंचने पर श्री अमित शाह के नेतृत्व में एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान श्री शाह का पांच चौक पर जोरदार स्वागत किया गया।

भाजपा कार्यालय में श्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, इसके साथ ही उन्होंने नानाजी देशमुख की याद में बनाई गई पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। ■

'मोदीजी के नेतृत्व में देश में एक विकास यात्रा की शुरुआत हुई है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 मई को तेलंगाना के नलगोंडा जिले के तेरत्पल्ली गांव में आयोजित बूथ कमिटी मीटिंग को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाने की अपील की। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष कार्य विस्तारक योजना के अपने 15 दिनों के कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय तेलंगाना प्रवास पर थे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 110 दिनों के देश के सभी राज्यों में विस्तृत प्रवास कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने शहीद हो जाने वाले प्रदेश भाजपा महासचिव एवं ओजस्वी कार्यकर्ता श्री जी मैसैया जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने बूथ-स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए डोर-टू-डोर कैम्पेन कर जनसंपर्क किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तीन साल की उपलब्धियों पर घर-घर बुकलेट भी बांटीं। इस दौरान उन्होंने दलित बस्ती में भोजन किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि नलगोंडा जिले के तेरत्पल्ली गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार से विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज एक ही मंच पर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए तेरत्पल्ली गांव किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, यही वह गांव है जहां हमारे कर्मठ नेता श्री जी मैसैया जी पार्टी का काम करते-करते शहीद हो गए थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह मैं तीन दिन तक तेलंगाना में तीन गांव और तीन बूथों पर जाकर संगठन की मजबूती और संगठन के विस्तार के लिए काम करूंगा, उसी तरह देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लगभग चार लाख कार्यकर्ता पूर्णकालिक के रूप में 15 दिन, 6 महीना एवं वर्ष भर के लिए बूथ-बूथ जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदेश एवं श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को हर घर पहुंचाने वाले हैं और संगठन की मजबूती के लिए काम करने वाले हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश के हर गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनायें लेकर आई है, लेकिन इनमें से कोई भी योजना तेलंगाना के गांवों में सही तरीके से नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि मैं अभी गांवों में कुछ गरीबों के घर में, गरीब बुनकरों के घर में संपर्क के लिए गया तो पता चला कि केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना किसी भी घर तक अभी भी नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग चार करोड़ से अधिक टॉयलेट्स

का निर्माण हो चुका है लेकिन तेरत्पल्ली गांव के गरीब घरों में अभी भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की राज्य सरकार केंद्र सरकार की गरीब-कल्याण योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचा रही है।

श्री शाह ने कहा कि आज इस अवसर पर मैं पूरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तेलंगाना के घर-घर जाएं और तेलंगाना को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास यात्रा चल पड़ी है। मैं तेलंगाना की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी की इस विकास यात्रा में तेलंगाना की जनता भी जुड़ जाएँ और राज्य को नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।

पेड्डा देवुलपल्ली गांव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तेलंगाना प्रवास के दूसरे दिन 23 मई को नलगोंडा जिले के पेड्डा देवुलपल्ली गाँव में बूथ कमिटी मीटिंग को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाने

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास यात्रा चल पड़ी है, मैं तेलंगाना की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि मोदीजी की इस विकास यात्रा में तेलंगाना की जनता भी जुड़ जाएं और राज्य को नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।

की अपील की। ज्ञात हो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष कार्य विस्तारक योजना के अपने 95 दिनों के कार्यक्रम के तहत अपने तीन दिन के दौरे पर तेलंगाना में थे।

इससे पहले उन्होंने वेलुगुपल्ली गाँव के दलित बस्ती दीनदयाल कॉलोनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण किया। वेलुगुपल्ली गांव से वे नलगोंडा ग्रामीण मंडल के चिन्नमदरम गाँव पहुंचे जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस गाँव और आसपास के गांव के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करवाने वाली भाजपा की महिला सरपंच श्रीमती पिंडी भाग्यम्मा जी का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गरीब-कल्याण की सोच को सच्चे अर्थों में साकार करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। विदित हो कि इस गांव की पूरी आबादी के पास जन-धन अकाउंट है और सभी परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे हैं। गाँव के कुल 584 घरों में से 300 घरों में शौचालय बनाने का काम पूरा हो चुका है और बाकी 284 घरों में भी शौचालय निर्माण का काम प्रगति पर है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। साथ ही, पूरे गांव में कंक्रीट सड़कें हैं। श्री शाह इसके बाद पेड्डा देवुलपल्ली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घर-घर जाकर डोर-टू-डोर कैम्पेन किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तीन साल की उपलब्धियों पर बुकलेट भी बांटीं। इस दौरान उन्होंने पेड्डा देवुलपल्ली गांव के एक दलित श्री वेंकन्ना जी के घर पर भोजन किया।

गुंड्रमपल्ली गांव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तेलंगाना प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन 24 मई को नलगोंडा जिले के नकिरेकल (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र के गुंड्रमपल्ली गांव में बूथ कमिटी मीटिंग को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाने की अपील की।

इससे पहले उन्होंने गुंड्रमपल्ली गांव में निजाम शासन के दौरान निजाम की प्राइवेट आर्मी (रजाकारों) के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले वीर योद्धाओं को सम्मानित किया। विदित हो कि निजाम शासन के समय निजाम की प्राइवेट आर्मी (रजाकारों) ने गुंड्रमपल्ली गांव के सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके मृत शरीर को कुओं में दफना दिया था। इस कार्यक्रम के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुंड्रमपल्ली गांव में बूथ संख्या 15, 16 और 17 में डोर-टू-डोर कैम्पेन किया। घरों पर स्टीकर चिपकाए और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों के बुकलेट भी बांटीं। बूथ कमिटी मीटिंग को संबोधित करने के बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ कई विषयों पर पारस्परिक चर्चा की और उनकी समस्याओं को नजदीक से अनुभव किया। इसके बाद वे यदाद्रि भुवनगिरि जिले के मुख्यालय भोंगिर पहुंचे जहां उन्होंने दलित बस्ती इंद्रा कॉलोनी में दोपहर का भोजन किया। श्री शाह ने भोंगिर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज्य में संगठन के विस्तार के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की।

गुंड्रमपल्ली गांव में बूथ कमिटी मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मैं अपने तीन दिन के तेलंगाना प्रवास के दौरान राज्य में जहां भी गया, मैंने महसूस किया कि तेलंगाना के लोगों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गजब का उत्साह है। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य के लोगों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विकासोन्मुखी व गरीब-कल्याणकारी नीतियों में अटूट श्रद्धा व विश्वास दिखाई दिया। ■

'आंध्र प्रदेश को भाजपा का मजबूत गढ़ बनायेंगे'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 मई को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित महासंकल्प बूथ अधिवेशन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से आंध्र प्रदेश को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने की अपील की। राज्य के 25 हजार से ज्यादा बूथों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेने इस अधिवेशन में आये। ज्ञात हो कि श्री शाह सभी राज्यों के अपने 110 दिवसीय विस्तृत प्रवास योजना के तहत आज एक दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश में थे। विदित हो कि उनका आंध्र प्रदेश में तीन दिन का विस्तृत प्रवास आगामी अगस्त महीने में प्रस्तावित है। इससे पहले आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य से राज्यसभा सांसद एवं केन्द्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी द्वारा अपनी सांसद निधि से राज्य के सभी 13 जिलों के लिए शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी और माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी भी उपस्थित थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई काम किये हैं। उन्होंने कहा की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आईआईटी, आईआईएम्, कृषि विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एनसीईआरटी सेंटर देने के साथ साथ राज्य में मेडिकल सीटों में 950 से अधिक का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में पहले से चल रही इंजीनियरिंग एवं हेल्थ एकेडमी के अपग्रेडेशन के लिए अलग से करोड़ों रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2000 एकड़ भूमि में एक मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर भी केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य में एक दूरदर्शन केंद्र, एक आकाशवाणी केंद्र और विजयवाड़ा में पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कोलावरम प्रोजेक्ट का पूरा खर्च भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उठाने वाली है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता तो केवल बोल कर चले गए थे, जबकि कोलावरम की चिंता भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये के हाइवे के प्रोजेक्ट्स शुरू किये हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में तीन हजार किलोमीटर लंबी सड़क का

निर्माण केन्द्र सरकार की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आंध्र में लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से रिफायनरी प्रोजेक्ट्स लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनंतपुर जिले में 7650 करोड़ रुपया, वायुसेना के इन्फ्रा के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि और डीआरडीओ के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट्स शुरू किये गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्पात संयंत्र के लिए राज्य में 38,500 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त परियोजना की शुरुआत की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेलवे में 450 करोड़ रुपये की लागत से एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं और रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया गया है, साथ ही, तिरुपति एवं राज्य के अन्य एयरपोर्ट्स के अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपये की राशि आवंटित की गई है।

आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आजादी के 70 साल तक आंध्र प्रदेश में जितना विकास केंद्र की अन्य सरकारों ने नहीं किया, उतना इन तीन वर्षों के अंदर नरेन्द्र मोदी सरकार ने करके दिखाया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग में कांग्रेस की सरकार ने स्पेशल स्टेटस पर एक प्रकार से कानूनी बैन लगा दिया था, इसलिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सका, लेकिन हमने इसके लिए भी अलग से रास्ता निकाला

है। उन्होंने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के लिए जो स्पेशल पैकेज नरेन्द्र मोदी सरकार लेकर आई है। उससे आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिलने की तुलना में एक रुपये का भी नुकसान नहीं होने वाला है, इसका विश्वास आंध्र प्रदेश की जनता को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए मोदी सरकार लगभग 175000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं और फायदे ले कर आई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आगामी जुलाई में आंध्र प्रदेश में होने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने जिस दिन प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश की पवित्र धरती पर कदम रखेंगे, उस दिन शाम को सात बजे पूरे आंध्र प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर दीये जलाएंगे, शंखनाद करेंगे और रंगोली बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वागत करेंगे।

विगत तीन वर्षों से सदस्यता अभियान के माध्यम से आंध्र प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद है कि पार्टी ने राज्य के 42 हजार बूथों में से 25 हजार से अधिक बूथों की रचना का काम पूरा कर लिया है।

विजयवाड़ा में महासंकल्प बूथ अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मैं आज इस अधिवेशन में आये हुए हजारों बूथ प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि विजयवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के इस महासंकल्प बूथ अधिवेशन से आंध्र प्रदेश में भाजपा की विजय यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि इसी पवित्र भूमि पर भगवान् शिव ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया था और इसी पशुपति अस्त्र से अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा का यह अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति अस्त्र जैसा साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब माँ कृष्णा (नदी) को सागर में जाने का रास्ता नहीं मिला तब अर्जुन ने पहाड़ में छेद करके यहीं से रास्ता निकाल कर माँ कृष्णा को सागर से मिलाया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय के सागर से मिलाने का काम यही बूथ अधिवेशन करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब मैं गत वर्ष आंध्र प्रदेश आया था तो मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनेगा। आज मैं फिर से यह कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ बनने वाला है।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विगत तीन वर्षों से सदस्यता अभियान के माध्यम से आंध्र प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद है कि पार्टी ने राज्य के 42 हजार बूथों में से 25 हजार से अधिक बूथों की रचना का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विकास ऐसे ही एक-एक कार्यकर्ता को जोड़कर हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी 10 सदस्यों के साथ शुरू होने वाली पार्टी आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है, आज भाजपा के 1387 विधायक देश की अलग-अलग विधान सभाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे 330 से अधिक सांसद दोनों सदनों में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 13 राज्यों में आज हमारे सरकार है, चार राज्यों में हम सहयोगियों के साथ सरकार में भागीदार हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में आज देश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है।

श्री शाह ने कहा कि दो दिन में ही मोदी सरकार अपने तीन वर्ष पूरा करने वाली है। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश को सम्मान दिलाने वाले कई सारे काम किये हैं - देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना, 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करना, हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाना, दो करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन पहुंचाना, सात करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना जैसे कई कार्य मोदी सरकार ने किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास एवं गरीबों के कल्याण के लिए 106 नई योजनाओं की शुरुआत की है।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश के हर गांव, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हो जाती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। उन्होंने कहा कि राज्य में तेलुगुदेशम पार्टी के साथ हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है, हमारे दोनों मंत्री भाजपा-टीडीपी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग को तो अच्छे कामों के लिए कई सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिवेशन में भाग लेने आये कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि में आंध्र प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। ■

मोदी सरकार के तीन साल

विदेश में धाक तो देश में साख

प्रभात झा

आजादी के 70 साल बीत रहे हैं। देश ने अनेक सरकारों को देखा है। आम जनता को सभी केन्द्रीय सरकारों के खट्टे-मीठे अनुभव प्राप्त हुए हैं। एक समय था जब विपक्ष सोच भी नहीं सकता था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर सत्तासीन हो सकेगा, लेकिन लंबे समय तक विपक्ष में रहनेवाली पार्टी को जनता-जनार्दन ने अधिकांश राज्यों सहित केंद्र में भी व्यापक जनसमर्थन दिया है। प्रतिकूलता में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और अनुकूलता में मर्यादा और विनम्रता की आवश्यकता होती है।

16 मई और 26 मई 2014- यह तिथि भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। भारतीय राजनीति और भारत की सरकार को स्थायित्व देने का सुनहरा समय प्रारंभ हुआ। समय किसी का सहोदर नहीं होता है। वह तो आता है और चला जाता है। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन वर्षों के कार्यों और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यों का अवलोकन करते हैं तो लगता है कि मोदी सरकार आध्यात्मिक समाज के भगवान श्रीराम

आम आदमी का जीवन भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त हो गया था। तीन साल में कालेधन पर रोक, भ्रष्टाचार से मुक्ति और बेनामी संपत्ति पर अलीगढ़ का ताला लगाने का जो सफलतम प्रयास मोदी सरकार ने किया है वह हर जुबां पर है। कालेधन से मुक्ति के लिए विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक फैसला किया गया।

के मर्यादाओं से बंधकर जनहितार्थ कार्य करने में लगे हुए हैं और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भगवान श्रीकृष्ण के पथ पर चलकर नयी राजनीति से दल का विस्तार करते हुए परिणाम तक ले जाने में

जुटे हुए हैं।

वर्षों से भाजपा पर अगड़ों और अमीरों की पार्टी होने का ग्रहण लगता रहा। मोदी सरकार और भाजपा संगठन ने पिछले तीन वर्षों में इस मिथक को तोड़ते हुए हर गरीब के घर-घर में यह बात पहुंचाने का सफल प्रयास किया है कि मोदी सरकार और भाजपा संगठन गरीबों की पार्टी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली पार्टी है।

'गरीबी हटाओ' जैसे नारे आजादी के बाद कांग्रेस देती रही, लेकिन गरीबी हटी नहीं। भाजपा ने न नारा दिया, न वादा किया। प्रधानमंत्री ने संसद की चौखट पर माथा टेकते हुए पहला वाक्य कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है और अपने पहले वाक्य को अभी तक जमीन पर साकार करने के लिए मोदी सरकार का हर फैसला साकार होता दिख रहा है।

भारतीय समाज को पहली बार यह अहसास हो रहा है कि निर्वाचित सरकार हमारी है। सरकार की सफलता पहले पायदान पर उस समय समझ में आती है कि जब समाज यह कहने लगे कि जो हम सोच रहे हैं वही सरकार कर रही है।

देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था। घोटालों की गूंज से संसद गूंजती रहती थी। आम आदमी का जीवन भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त हो गया था। तीन साल में कालेधन पर रोक, भ्रष्टाचार से मुक्ति और बेनामी संपत्ति पर अलीगढ़ का ताला लगाने का जो सफलतम प्रयास मोदी सरकार ने किया है वह हर जुबां पर है। कालेधन से मुक्ति के लिए विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक फैसला किया गया। विमुद्रीकरण की परीक्षा में नरेन्द्र मोदी जहां शत-प्रतिशत सफल हुए हैं, वहीं गरीबों ने अपनी आवाज से सरकार के साथ आवाज मिलाकर दो-टूक लोकतांत्रिक फैसला दिया कि विमुद्रीकरण पर मोदी सरकार के साथ हैं। इतना कठोर निर्णय! गरीब से गरीब को कठिनाई हुई, लेकिन

सबके मन में एक खुशी थी कि कालाधन और भ्रष्टाचार रोकने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है।

विपक्षी पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया? मैं उनको कहना चाहता हूं कि तीन साल में 49 करोड़ लोगों से अधिक को सीधा लाभ पहुंचाने और उनके सिर्फ बैंक खाते ही नहीं, बल्कि तकदीर के खाते खोलने का काम किया है। कुछ आंकड़े- जनधन-योजना के तहत 27.97 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में इन गरीबों ने स्वयं 63.835 करोड़ रुपए जमा किए। अब इन खातों में सरकारी योजनाओं की राशि जाने लगी। 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया। स्टार्टअप एवं स्टैण्डअप योजना के तहत मुद्रा योजना के माध्यम से 6.6 करोड़ लोगों ने ऋण

प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल करने के लिए बैंक के ब्याज दरों में कमी और 2022 तक 5 करोड़ आवासहीन लोगों के सपने को साकार करने की दिशा में जो कदम उठाया जा रहा है, वह ऐतिहासिक कहा जाएगा। 12 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करोड़ों हाथों को हुनर देने के लिए स्वयं आगे आ रहा है।

लिये और व्यापार शुरू किया। उज्ज्वला योजना के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे 2 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। यह उज्ज्वला यही नहीं थमेगी, आनेवाले वर्षों में 5 करोड़ लोगों के घर की धुआं बंद करेगी।

क्या किया तीन साल में, विपक्षी पूछते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद स्वच्छ भारत को अगर किसी ने जनांदोलन बनाया तो वह है नरेन्द्र मोदी की सरकार ने। स्वच्छता, समाज को स्वस्थता की ओर ले जा रही है। स्वच्छ भारत का अभिप्राय है स्वस्थ भारत। सामान्य सी बात लगती है, लेकिन उजाला एलईडी योजना, जिसके पीछे बिजली बचाओ अभियान है, इसके तहत 11 करोड़ 8 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल करने के लिए बैंक के ब्याज दरों में कमी और 2022 तक 5 करोड़ आवासहीन लोगों के सपने को साकार करने की दिशा में जो कदम उठाया जा रहा है, वह ऐतिहासिक कहा जाएगा। 12 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करोड़ों हाथों को हुनर देने के लिए स्वयं आगे आ रहा है।

मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। किसान यदि सुरक्षित नहीं तो भारत सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा राशि दुगुनी कर दी और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के दुगुने स्तर पर लाया गया। अब तक देश के 3 करोड़ 86 लाख किसानों ने इस योजना के तहत अपने को सुरक्षित किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत 'हर खेत को पानी' के लिए पिछले दो वर्षों से 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसान की आय दुगुनी करने के लिए जबर्दस्त योजना बनाई गई है। 'अच्छे दिन आएंगे' ये नारा नहीं है। अच्छे दिन आ रहे हैं। 31 मार्च 2014 को उपभोक्ता महंगाई दर 9.46 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2017 को तीन साल के अंदर घटकर 3.81 प्रतिशत हो गई है। ये आंकड़े भारत के हैं, भाजपा के नहीं। 31 मार्च 2014 को जीडीपी जो 6.7 प्रतिशत थी वह 31 मार्च 2017 को 7.10 प्रतिशत हो गई। 31 मार्च 2014 को औद्योगिक उत्पादन दर नकारात्मक -0.10 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2017 को 3 साल के अंदर बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई है।

सड़कों की बात करें तो एक लाख बीस हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कोई सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2016-17 में 48,000 किमी सड़क निर्माण हुआ और हर रोज 133 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2013-14 में रोजाना 69 किमी सड़क का ही निर्माण होता था।

इतना ही नहीं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से निम्न और मध्यम वर्ग के शोषण का खात्मा हुआ। मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों और विभागों की 92 योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू होने से 49,560 करोड़ की बचत हुई।

संघीय व्यवस्था को मजबूत किया गया। एक राष्ट्र-एक कर (जीएसटी) को लागू कर और जीएसटी के लिए नेशनल काउंसिल बनाकर निर्णय लेने का जो फोरम बनाया गया वह संघीय व्यवस्था को मजबूत करता है।

मोदी सरकार का सपना है कि हर व्यक्ति को छत मिले। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा घर मोदी सरकार में मिले हैं और 17,73,533 किफायती घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।

महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिले लाभों में 79 प्रतिशत महिलाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से 1 करोड़ खाते खोले गए और कुल 11,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम अत्यंत सफल कार्यक्रम साबित हो रहा है। मोदी सरकार ने गरीब की रसोई को धुआं मुक्त कर दिया है और अब तक 2 करोड़ 20 लाख गरीब परिवार की माताएं-बहनें इसका लाभ ले रही हैं।

मोदी सरकार की प्राथमिकता है युवाओं का विकास और प्रोत्साहन। स्टार्टअप्स अभियान के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे युवा अब केवल नौकरी नहीं मांग रहा है, अपितु व्यवसाय कर वह रोजगार सृजन में भी जुट रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है तथा 34 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त किया गया है। मोदी सरकार की अभिनव योजना 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ने उत्पादों की गुणवत्ता के मामले में चीन को सात स्थान पीछे धकेल दिया है।

मोदी सरकार सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। रिटायर्ड सैनिकों के हित में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चार दशकों से लंबित 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को पूरा किया। बांग्लादेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को मोदी सरकार ने सुलझाया। 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक से विश्व में देश की साख बढ़ी। इससे पहले म्यांमार में भी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया।

विधि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। 1100 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया और ऐसे ही 400 अन्य कानूनों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार में संविधान, सीमा और सेना का गौरव बढ़ा है। दुनिया भर में भारत की साख और धाक बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विदेश प्रवास से भारतवंशियों के बीच उत्साह जगा है। कैबिनेट के निर्णय और आंकड़ों पर जाएं तो शब्द और पन्ने कम पड़ जाएंगे।

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। इन राज्यों में 61 प्रतिशत आबादी रहती है, अर्थात् देश की दो तिहाई आबादी की सेवा एनडीए सरकार कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य की आबादी मात्र 9 प्रतिशत रह गई। कांग्रेस की केवल 6 राज्यों में सरकार है। इन राज्यों में केवल 8.6 प्रतिशत आबादी रहती है। भाजपा के 283 लोकसभा सांसद है। राज्य सभा में 56 सांसद हैं। एनडीए के 339 लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा में 74 सांसद हैं। 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई भाजपा 12 करोड़ सदस्य के साथ आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश में भाजपा के 1,398 विधायक हैं। अजजा और अजा के सर्वाधिक सांसद भाजपा के हैं। सर्वाधिक महिला सांसद भाजपा के हैं। सर्वाधिक महापौर भाजपा के हैं। सर्वाधिक जिला पंचायत और पार्षद भाजपा के हैं। सर्वाधिक गांव के सरपंच भाजपा के हैं। आने वाले दिनों में एनडीए राष्ट्र की पसंद का राष्ट्रपति चुनने वाला है।

विश्व के नामवर नेताओं में एक श्रेष्ठ नाम आता है नरेन्द्र मोदी का। अंग्रेजी में ग्लोबल और हिंदी में वैश्विक नेता का स्थान बनाने में उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। संगठन और सत्ता के समन्वय का इतिहास रचा जा रहा है। अनुकूलता के इस वर्चस्वशाली माहौल में देश की निगाहें भाजपा की ओर टिकी हुई हैं। कांग्रेस युग की समाप्ति का दौर चल रहा है। भाजपा युग के आगमन का दौर प्रारंभ हो चुका है। इस अनुकूल माहौल में हम सबका दायित्व बढ़ गया है। देश में अधिकारों की बजाय देश के लिए कर्तव्य करने का भाव पैदा हुआ है। तीन साल में भारतीय राजनीति ने अपनी खोई हुई साख को लौटाने की दिशा में एक नहीं, अनेक कदम उठाए हैं। मई 2014 के पहले रोज भ्रष्टाचार की चर्चा सदन में और सड़क पर होती थी, पर गत 3 वर्षों में न देश में, न संसद में, न सड़क पर मोदी सरकार में

तीन साल में भारतीय राजनीति ने अपनी खोई हुई साख को लौटाने की दिशा में एक नहीं, अनेक कदम उठाए हैं। मई 2014 के पहले रोज भ्रष्टाचार की चर्चा सदन में और सड़क पर होती थी, पर गत 3 वर्षों में न देश में, न संसद में, न सड़क पर मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप न लगना यह दर्शाता है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। देश न प्रधानमंत्री का है, न भाजपा का। देश भारत के सवा सौ करोड़ आबादी का है और उसकी सेवा का जो सुनहरा मौका मिला है, उस दिशा में भाजपा और भाजपा सरकार का कदम सदैव उठते रहना चाहिए।

भ्रष्टाचार का आरोप न लगना यह दर्शाता है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। देश न प्रधानमंत्री का है, न भाजपा का। देश भारत के सवा सौ करोड़ आबादी का है और उसकी सेवा का जो सुनहरा मौका मिला है, उस दिशा में भाजपा और भाजपा सरकार का कदम सदैव उठते रहना चाहिए। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद हैं।)

मोदी की आर्थिक नीतियां अधिक सुदृढ़: नये भारत की प्रेरणा

डॉ. आर. बालाशंकर

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में भारत ने विश्व आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में स्थान सुरक्षित किया है। भारत 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से विकास कर रहा है, जबकि विश्व की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत है। शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पहली बार भारत में बिजली और कोयले का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। ऊर्जा परिदृश्य काफी आशाजनक है। ऐसे समय में जब तेल की कीमत कम हो रही है, भारत सफलतापूर्वक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित कर रहा है। मुद्रास्फीति कम है। ऋण दरें कम हो गई हैं। अधिक ऋण लिया जा रहा है। देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सबसे अधिक सार्वजनिक निवेश हुआ है। सभी आर्थिक मूल सिद्धांत सतत् आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

मोदी सरकार ने असल में भारत की उस गौरव गाथा को दोबारा हासिल कर लिया है, जो नीतिगत पक्षाघात, घनिष्ट पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के कारण मलिन हो गई थी। श्री मोदी ने साबित कर दिया है कि अच्छा अर्थशास्त्र अच्छी राजनीति है। उन्होंने विकास को भारतीय राजनीतिक बहस का केंद्रीय विषय बना दिया है। वास्तव में यह वर्तमान सरकार के पिछले तीन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भारत सफलतापूर्वक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित कर रहा है। मुद्रास्फीति कम है। ऋण दरें कम हो गई हैं। अधिक ऋण लिया जा रहा है। देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सबसे अधिक सार्वजनिक निवेश हुआ है। सभी आर्थिक मूल सिद्धांत सतत् आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक हैं, जिसके परिणाम स्वस्त्र भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

यह पहले की राजनीति से काफी अलग है, जब राष्ट्रीय भाषणों में भावनात्मक, जाति, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और पहचान के मुद्दे छाये रहते थे। हाल ही के प्रत्येक चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया से राजनीतिक दल नैतिक रूख अपनाने और महत्वाकांक्षी भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री ने राजनीति को पुनः गढ़ा है। सबके साथ, सबका विकास यानी प्रत्येक व्यक्ति एक हितधारक के रूप में सबके विकास के लिए जिम्मेदार है।

इसके लिए मोदी सरकार टीम इंडिया की दिशा में आगे बढ़ी है, जहां प्रत्येक राज्य आर्थिक विकास का साधन बना है और निवेश को बढ़ावा देने तथा कारोबार में सुगमता लाने का वातावरण तैयार करने के लिए राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तर्ज पर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवंटन बढ़ा दिया है। वस्तुओं की संवैधानिक योजना में विकास, बिजली, पानी, सड़क, भूमि और शिक्षा जैसे सभी प्रमुख पहलू राज्य या समवर्ती सूची में हैं। नीति आयोग के माध्यम से नियोजन की भूमिका को दोबारा परिभाषित करना सकारात्मक विकास के लिए राज्यों की पहलों को बढ़ावा देने का कदम था। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों ने कृषि क्षेत्र में दोहरे अंकों की विकास दर हासिल कर राष्ट्रीय कृषि विकास की दर को बढ़ाया है।

सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इस कहानी का एक और पहलू है। आजादी के बाद से पहली बार सबसे अधिक संख्या में 35 करोड़

लोग बैंक खाताधारक बने हैं। ये सभी लोग स्वतः ही जीवन बीमा के लिए पात्र हो गए हैं। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा देने, दस मिलियन से अधिक परिवारों द्वारा सब्सिडी छोड़ने और गरीब परिवारों को सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए 55 हजार करोड़ रुपये की बचत से अधिक संख्या में लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना के जरिए आवास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर ऐसे लाखों लोगों के सपनों को साकार किया गया, जिन्हें कभी अपना घर होने या स्वयं का व्यापार शुरू करने की उम्मीद ही नहीं थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण से सात दशकों में पहली बार 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई। पिछली सरकार की मनरेगा और आधार जैसी अच्छी तथा व्यवहार्य योजनाओं को और सुदृढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन बीमा, सुरक्षा योजना तथा स्वास्थ्य अभियान, दवाओं और स्टेंट की कीमतों के नियमन जैसी नई कल्याणकारी पहलों से ग्रामीण जीवन शैली में क्रांति लाई गई है। इन उपायों से निम्न आय वर्ग के लोगों में आशा और विश्वास जगा है। विमुद्रीकरण अधिक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए धन के पुनर्वितरीकरण की दिशा में प्रमुख कदम था। इससे करोड़ों रुपये का कालाधन बाहर आया और करोड़ों रुपये की नकली मुद्रा समाप्त हुई।

मोदी सरकार ने तीन वर्षों में जो हासिल किया है, वह विकास की दृष्टिकोण से संपूर्ण सोच में परिवर्तन है। सरकार ने तेल सब्सिडी को समाप्त कर, सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाकर, बेहतर कर संग्रह, कोयला ब्लॉकों तथा स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ सुनिश्चित कर सार्वजनिक कोषों में भारी बचत की है, जिन्हें पिछली सरकार ने शून्य मूल्य संपत्ति बताया था। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने न केवल अपनी शपथ को कायम रखा कि वे एक पहरेदार के रूप में राष्ट्रीय खजाने की सुरक्षा करेंगे, बल्कि सार्वजनिक जीवन में घनिष्ठ संबंधों को भी समाप्त किया। नकद रहित समाज और डिजिटल लेनदेन के विचार की जड़ में विवेकपूर्ण आर्थिक योजना थी। सरकार का नीति संचालित, विश्वसनीय, लक्षित और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण रहा है। अधिकार, विशेषाधिकार और माई-बाप की सरकार का शासन अतीत की बात है। असल में शासन के प्रतिदिन के कार्यों में असली लोकतंत्र ताजी हवा का झोंका है, जो श्री नरेन्द्र मोदी राजनीति और शासन में लाए हैं।

इन वर्षों में भारत ने कारोबार करने में आसानी के सूचकांक में ऊपर का स्थान हासिल किया है। कुछ महीने पहले इंडिया ऑन लाइन शीर्षक से मुख्य कहानी में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, "प्रति सेकेंड तीन भारतीय पहली बार इंटरनेट का अनुभव करते हैं। 2030 तक उनमें से एक बिलियन से अधिक ऑनलाइन होंगे...भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और पृथ्वी पर सहस्त्राब्दि की सबसे अधिक आबादी यहां होने का दावा करता है ... और आप देख सकते हैं कि फेसबुक, उबर और गूगल जैसी कंपनियां यहां पर अपना आधार तैयार करने के लिए क्यों उत्सुक हैं...।" स्पष्ट है कि एनडीए के शासन के तहत भारत राजस्व गुणक और निवेश गंतव्य है तथा हाल ही में रोजगार बाजार में भी इसकी संभावनाएं बढ़ी है।

सफल स्टार्ट-अप्स से भारत विश्व का विनिर्माण केंद्र बन रहा है। लोकतंत्र, विश्वसनीय संस्थागत ढांचे, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रणालियों से भारत को चीन की तुलना में निवेशकों का विश्वास जीतने में मदद मिली है। श्री मोदी ने भारत के लिए एक नया पत्ता खोला है, जिसने 30 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत की विकास गाथा में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया और विदेशों से भेजी गई काफी धनराशि देश में आई। तीन वर्ष में श्री मोदी ने निराशा को आशा में बदल दिया है और जैसा कि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत अंधेरे समुद्र में एकमात्र सिल्वर लाइन है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय प्रकाशन विभाग के सदस्य हैं)

ईपीएफओ के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 16 मई को बेंगलुरू में ईपीएफओ के नागरिक चार्टर 2017 और ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। नागरिक चार्टर 2017 का उद्देश्य ईपीएफओ की ओर से होने वाले कामकाज में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे सेवा प्रदान करने से जुड़ी प्रणाली एवं शिकायत निवारण व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी, जिससे इसके समस्त हितधारकों को वस्तुओं एवं सेवाओं को समयबद्ध ढंग से मुहैया कराया जा सकेगा। इसके तहत निर्धारित समय सीमा भी कम हो जायेगी, जो वर्तमान में 30 दिन है।

दावा निपटान के मामले में समय सीमा 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के मामले में समय सीमा 15 दिन है। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने के विजन के साथ नागरिक या सिटीजन चार्टर को लांच किया गया है। इसका एक अन्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सहायता के साथ सभी हितधारकों के फायदे के लिए नीतियों को क्रियान्वित करना है।

ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य एक पारदर्शी एवं इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करना है जो सभी हितधारकों यथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों, याचिकाकर्ताओं और सीबीटी की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। ■

"देव, दवे को अभी नहीं बुलाना था"

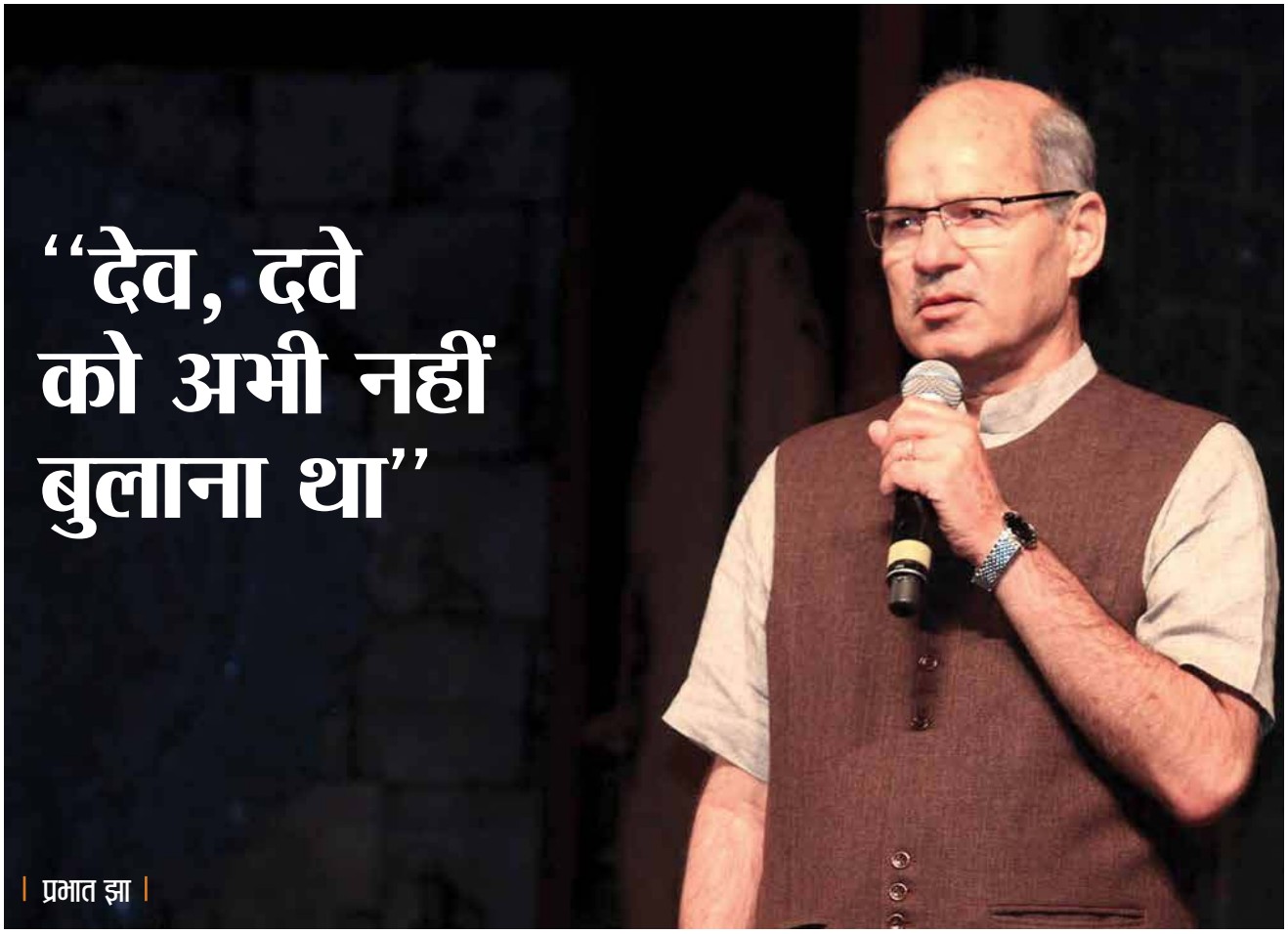

| प्रभात झा |

अनिल माधव दवे देव के पास चले गए। अभी नहीं जाना था। जाना तो सबको है पर किसी होनहार का असमय जाना आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। म.प्र. वे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बड़े साहब दवे के पौत्र थे। उज्जैन का बड़नगर उनका पारिवारिक गृह नगर रहा है। इन्दौर उनकी शिक्षा-दीक्षा का स्थान रहा। वे छात्र राजनीति में भी अग्रणी रहे। वहीं से वे संघ के प्रचारक भी थे। मृदुभाषी, संयमवाणी और परिणामकारी कार्य उनके जीवन की विशिष्टता थी।

मेरा उनका संपर्क लगभग 35 वर्षों का रहा। मैंने उन्हें संघ के प्रचारक के रूप में जहां इन्दौर में देखा, वहीं वे भोपाल में हमारे विभाग प्रचारक थे। कठोर जीवन जीने के वे आदी थे। नपे-तुले शब्दों में वार्ता उनका नैसर्गिक स्वभाव था। वे नेपथ्य के पथ्य थे। अनेक गुणों के गुणी होने के बावजूद वे अपेक्षारहित भाव से काम करने के आदी थे। वे काम के धुनी थे। ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करने में विश्वास करते थे। राजनीतिक क्षेत्र में जब वे आये तब उन्हें बहुत करीब से देखा। वे गणितज्ञ भाव से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते थे। उन्हें जो भी कार्य दिया गया, वे उस कार्य के चरित्र का अध्ययन करते थे, उसके बाद उस कार्य के चरित्र को अपने चरित्र से मेल-मिलाप कर कार्य को जमीन पर उतारते थे। अध्ययन, स्वाध्याय और विजयी भाव उनके स्वभाव में था। वे परास्त और अस्त की भावना से कोई कार्य नहीं करते थे। वे उदयजीत की भावना से किसी भी कार्य का प्रारंभ करते थे।

विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध, नैतिक साहस से युक्त और समय के साथ समयबद्ध रहकर कार्य के अनुरूप दवे जी व्यक्तियों को जुटाते थे। टोली बनाकर कार्य करना उनका स्वभाव था। वे समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने का प्रयत्न करते थे। समाज में व्याप्त प्रदूषण से ही उनका स्वभाव और प्रकृति पर्यावरण की ओर बढ़ा। वे प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति की पद्धति से जिनका वेद-पुराण और शास्त्रों में वर्णन है, से करने में विश्वास रखते थे। उनकी मूल मान्यता थी कि भारत की समस्याओं का निदान भारतीय पद्धति से होगा न कि पाश्चात्य पद्धति से। उनकी प्रकृति का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वे भोपाल में जहां रहते थे उसका नाम ही 'नदी का घर' रखा था। नदियों के संवर्धन और संरक्षण को उन्होंने अपने जीवन के कार्य की प्राथमिकता में रखा था।

बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि अनिल माधव दवे जी

हवाई-जहाज के पायलट थे। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया भी, लेकिन समाज की पीड़ा और दयनीय स्थिति ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया कि जहाज उड़ाने से अच्छा समाज के पीड़ितों के लिए जमीन पर रह कर काम किया जाये। वे संघ से जब राजनीति में आए तो उनका पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पड़ा, जो लगातार 10 वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्हें राजनीतिक तौर पर परास्त करना कठिन था। लेकिन उमा भारती जी के नाम को आगे कर राजनीतिक युद्ध की सारी तैयारियां एक छोटे से बंगले में बैठकर दवे जी ने बनाई और 2004 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। तब से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए वे हर चुनाव में मुनष्य के शरीर में जिस प्रकार हड्डी की भूमिका होती है, उसका कार्य उन्होंने किया। वे अक्सर कहा करते थे कि किसी भी युद्ध को जीतने की आधी संभावना तब बन जाती है जब अंतिम दिन तक की कार्ययोजना बन जाती है।

दवे जी बहुगुणी थे। उनको लेखक के रूप में भी स्वीकार्यता मिली। उनके जीवन पर छत्रपति शिवाजी का प्रभाव था। उन्होंने उन पर एक पुस्तक शिवाजी व सूरज लिखी। दूसरी पुस्तक 'सोलह संस्कार' और तीसरी पुस्तक 'अमरकंटक से अमरकंटक' लिखी। जब वे न सांसद थे न मंत्री तब भी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहना उनकी मूल प्रकृति थी। वे विश्वपटल पर पर्यावरण के अनेक सम्मेलनों में पर्यावरणिवद् के नाते न केवल भाग लेते थे, पर्यावरणविद् पुरोधा बनकर इस बात को जोर से रखते थे कि प्रकृति संस्कृति की रक्षा भारतीय संस्कृति से ही हो सकती है। उन्होंने बांध्रभान में ही अपने रहने के लिए मां नर्मदा के किनारे आश्रम बनाया। आश्रमी स्वभाव से ही उस आश्रम में रहते थे। उनके जीवन में दो ऐसे अवसर आए जिसने उन्हें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थ बनाया। भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मेलन और उज्जैन के महाकुंभ में वैचारिक कुंभ के आयोजन में उनकी भूमिका केन्द्र बिन्दु में थी। उनकी इस प्रकृति को देखकर ही प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के फेर-बदल में उन्हें पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया।

दवे जी जीवटधारी व्यक्ति थे। उनकी जीवटता का अनोखा उदाहरण समाज के समक्ष रखना जरूरी है जो हम सभी को प्रेरणा देगा। डॉक्टरों ने कुछ वर्ष पहले उन्हें कहा कि आप हृदय के रोगी हैं और आपका ओपन हार्ट सर्जरी होना है। दवे जी ने किसी को इसकी जानकारी न देते हुए डॉक्टर से कहा मुझे कहां आपरेशन के लिए जाना है। डॉक्टरों ने कहा कि मुंबई में कराना है। वे अपने सहयोगी को लेकर मुंबई गए और डॉक्टर से कहा कि मेरे ऑपरेशन की तिथि तय कीजिए। डॉक्टर ने पूछा आपके घर वाले कहां हैं तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मेरा है मैं उपस्थित हूं। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थियेटर ले गए और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जब वे होश में आए तो अपने सहयोगी को कहा कि सबको बताओ कि मुंबई में मेरी हार्ट सर्जरी हो गई। जीवटता का ऐसा अनुपम उदाहरण शायद ही मिल सके।

दवे जी अनोखे थे। सामान्य परिवार के होने के बावजूद असामान्य और असाधारण कार्य करना उनकी विशेषता थी। लगातार उनके साथ रहने और कार्य करने के कारण लगता है कि उन्हें अभी और रहना चाहिए था, पर मनुष्य और विज्ञान यहीं परास्त हो जाता है। हर अस्त का उदय होता है। अनिल माधव दवे अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी देह का अस्त हुआ है। उनकी देह का उदय होगा और वह देह जग को जग-मग जरूर करेगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद हैं)

डॉ. हर्षवर्धन ने पर्यावरण मंत्री का पदभार ग्रहण किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 22 मई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। पिछली 18 मई को केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे का आकस्मिक निधन हो गया था। डॉ. हर्षवर्धन ने आईपी भवन के परिसर में स्वर्गीय अनिल माधव दवे की याद में एक पौधा लगाकर अपने कार्य की शुरूआत की। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मंत्री पद पाकर अनुगृहीत हैं तथा स्वर्गीय अनिल माधव दवे को याद करते हुए कहा कि वे नदी संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति समर्पित थे। श्री दवे पर्यावरण का संरक्षण बच्चों के लिए करना चाहते थे। इसमें बच्चों के प्रति उनका स्नेह दिखाई पड़ता है। श्री दवे जी ने देश की नदियों, वनों तथा पारितंत्र के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किया। पर्यावरण के प्रति उनका यह समर्पण उन्हें एक महान पर्यावरणविद बनाता है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि श्री अनिल माधव

दवे कहा करते थे, 'यदि मैं कर सकता हूं तो हम सभी कर सकते हैं।' मंत्री महोदय ने कहा कि मंत्रालय, स्वर्गीय श्री दवे की अंतिम इच्छा- पौधे लगाने, पेड़ों को पोषित व संरक्षित करने तथा नदियों व तालाबों की सफाई व रखरखाव- को सदैव याद रखेगा। ■

सुधारों के सिलसिले ने बदली तस्वीर

अमिताभ कांत

भारत की व्यापक और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार को लेकर आजादी के बाद साठ के दशक से ही चर्चा होती रही है। हाल के समय में देश में दो प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 और 2005 में गठित किए गए। दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन उनकी कई सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं हो सका है, किंतु पिछले तीन वर्षों में ऐसी कई नई पहल की गई हैं जिनसे पता चलता है कि सरकार प्रशासन में सुधार की गति को तेज करना चाहती है और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक कुशल, निर्णायक एवं समावेशी बनाना चाहती है। इनमें योजनाओं की परिणाम आधारित निगरानी, उच्चतम स्तर पर परियोजनाओं में तेजी लाना, राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, मंत्रालयों के एकांगी रूप से काम करने की प्रवृत्ति को तोड़ना और सरकार में प्रतिभाओं का समावेश करना शामिल है। पिछले तीन सालों में पहला महत्वपूर्ण सुधार यह हुआ है कि प्रशासनिक ध्यान इनपुट और आउटपुट से हटकर परिणाम पर केंद्रित हो गया है और उसकी समीक्षा और निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। आम आदमी को प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, समितियों के गठन आदि से कोई लेना-देना नहीं होता, उसे तो बस परिणाम चाहिए। स्वाभाविक तौर से नागरिक केंद्रित और सहभागितापूर्ण शासन व्यवस्था सृजित करने के लिए पहला कदम यही हो सकता है कि व्यवस्था को परिणामोन्मुख बनाया जाए। जहां सड़क परियोजनाओं का आकलन क्षमता, गतिशीलता, गुणवत्ता और सुरक्षा के पैमाने से किया जा रहा है, वहीं रेलवे के मामले में परिचालन अनुपात, यात्री और माल ढुलाई से होने वाली प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उपायों को मुख्य पैमाना माना गया है। सुधारों के तहत ही पहली बार नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया परिणाम आधारित बजट मुख्य बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया।

परिणाम आधारित समीक्षाएं कई क्षेत्रों में की जा रही हैं। कुल बजट परिव्यय में 72 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले 15 बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद कई निर्णय भी लिए गए। जैसे वित्त वर्ष 2017 में रेलवे के शेयर को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया, ताकि 2032 तक इसे 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सांस्थानिक सुधार के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद की भी समीक्षा की गई है। समिति ने काफी बदलावों की सिफारिश करते हुए एमसीआइ की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाने का प्रस्ताव किया है, ताकि इंस्पेक्टर राज की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो और चिकित्सा शिक्षा में बड़े सुधार किए जा सके।

दूसरी महत्वपूर्ण पहल है 'प्रगति' यानी सक्रिय शासन और समयबद्ध

कार्यान्वयन। यह एक ऐसी पहल है जिसके तहत बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र की ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री के स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जा रही है जिनके अमल में दिक्कतें आ रही हैं अथवा जिनके पूरा होने में देरी हो रही है। 'प्रगति' की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे यह चुनिंदा परियोजनाओं के सभी पक्षों को अपने विचार रखने और मुद्दों के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराता है, अधिकारियों को स्पष्ट और निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किए जाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपता है, केंद्र और राज्यों को एक ही मंच पर लाकर विकास परियोजनाओं में तेजी लाता है।

इससे मुख्य परियोजनाओं पर देश के सर्वोच्च अधिकारियों की निगरानी बनी रहती है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच के गतिरोध को भी खत्म करता है। इसके जरिये सर्वोत्तम कार्यशैलियों को साझा करना भी संभव हो पाता है। अब तक 18 'प्रगति' बैठकें हो चुकी हैं और 8.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राज्य परियोजनाओं की गति को तेज किया गया है। रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली, कोयला, नागर विमानन से जुड़ी ये परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से देरी से चल रही थीं। इस पहल से विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं की गति में तेजी आई है। परियोजनाओं के अलावा, 16 मंत्रालयों/विभागों के 38 अग्रणी कार्यक्रमों, योजनाओं और शिकायतों की भी समीक्षा की गई है। उदाहरण के लिए नांगल बांध तलवाड़ा रेलवे लाइन 1981 से ही लंबित थी, लेकिन अब इसमें तेजी लाई गई है। 'प्रगति' के लागू होने के बाद से अफगानिस्तान में सलमा बांध, पटना में गंगा पर रेल-सह-सड़क सेतु, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय महापंजीयक के आधार नामांकन में काफी तेजी आई है। 'प्रगति' कई अर्थों में एक अनूठी व्यवस्था साबित हुई है। इसने केंद्र और राज्य के बीच दीवारों को तोड़ा है, परिणाम और लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया है और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पारदर्शी मंच उपलब्ध कराया है।

तीसरा प्रमुख प्रशासनिक सुधार रैंकिंग के जरिये राज्यों और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने का है। व्यवसाय करने की सुगमता की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग के फलस्वरूप राज्य सरकारों ने मूलभूत सुधार करने शुरू कर दिए हैं। प्रतिस्पर्द्धा के दबाव ने तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। स्वच्छ भारत पहल के तहत स्वच्छता की दृष्टि से जिलों की रैंकिंग का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसने नगर निकायों के स्तर पर बदलाव को प्रोत्साहित किया है।

चौथा मुख्य सुधार सचिवों के समूहों का गठन करना रहा है। पिछले वर्ष विभिन्न विषयों पर आठ 'सचिव समूहों' का गठन किया गया था। इन समूहों को संयुक्त सचिवों के इसी प्रकार के समूहों द्वारा सहायता प्रदान की गई। इन समूहों का एक अनूठा पहलू यह था कि इनमें ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया, जिनके विभाग इन विषयों से सीधे संबंधित नहीं थे। इसने रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया। इस वर्ष इन समूहों को अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित कराने का दायित्व सौंपा गया है।

जब तक मनोवृत्तियां नहीं बदलतीं तब तक सुधार संभव नहीं होता। नए चिंतन और नवोन्मेषी विचारों को लाने के लिए अनेक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। संसाधनों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने वाले योजना आयोग को समाप्त करने, 1175 पुराने कानूनों को समाप्त करने, रेल और संघीय बजट को मिलाने जैसे सभी कदम भारत को व्यवसाय करने की दृष्टि से सरल और सुगम स्थान बनाने और शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं।

वार्षिक बजट में योजना और गैर-योजना व्यय के बीच भेद को समाप्त करने जैसे उपायों से राजस्व घाटे को कम करने की बजाय पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सुधारों के तहत ही निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को सरकार के माध्यम से सार्थक बदलाव लाने का मौका देने की भी शुरुआत की गई है। ऐसे अनेक युवाओं ने डीजिधन मेलों में अपना योगदान दिया था। हालांकि इन सभी सुधारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने में समय लग सकता है, लेकिन उनकी दिशा सही और गति तेज है। प्रशासनिक सुधारों की इस सतत प्रक्रिया का ही यह परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में बिना किसी आडंबर के काफी कुछ हासिल किया गया है। स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा। ■

(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं)

मोदी सरकार के तीन वर्ष
निराशा से नई आशा की ओर: एम. वेंकैया नायडू

केंद्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने अनेक ट्वीट कर कहा कि ''मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पहले से अधिक निश्चय और एकजुट किया है। लोग निराशा से बाहर निकले हैं और देश नए क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में मिले जनादेश के अनुरूप रचना हो रही है। धन्यवाद टीम इंडिया। तीन वर्ष के निर्णायक, ईमानदार, देखभाल करने वाले, विचारशील, प्रगतिशील,उत्तरदायी और सशक्त सुशासन ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से भरे नए भारत की बुनियाद रखी है। गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को सशक्त किया गया है और देश और देशवासियों के सामर्थ्य की शुरूआत हुई है। मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल ने हर नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व का अनुभव हुआ है। स्वयं और नेतृत्व पर विश्वास पुनः स्थापित होने से देश विकास की नई ऊंचाईयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सशक्त कर देशवासियों की आशाओं और उम्मीदों के नए देश की मजबूत बुनियाद रखी गई है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री नायडू ने ट्वीट कर कहा कि "तीन

वर्षों के शहरी सुधार कार्यक्रमों ने पुनरुत्थानशील शहरी भारत के निर्माण के लिए शहरों और राज्य सरकारों में नया जोश भरा है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे शहर उन्नत शहरी जीवन की आशा का संचार करते हैं। धन्यवाद टीम इंडिया। पहली बार 500 अमृत शहर और 98 स्मार्ट शहरों के पास शहरी आधारभूत ढांचे और जीवन स्तर में बदलाव के लिए पांच वर्ष की कार्ययोजना है। गत तीन वर्षों में शहरी आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए चार लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश को अनुमति प्रदान की गई है। ■

सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के तीन साल के काम-काज को ले कर चल रही समीक्षा का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 15 दिन, महीने से, लगातार अख़बार हो, टी.वी. चैनल हो, सोशल मीडिया हो, वर्तमान सरकार के 3 वर्ष का लेखा-जोखा चल रहा है। 3 साल पूर्व आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व दिया था। ढ़ेर सारे सर्वे हुए हैं, ढ़ेर सारे ओपीनियन पोल आए हैं। मैं इस सारी प्रक्रिया को बहुत ही स्वस्थ्य चिह्न के रूप में देखता हूं। हर कसौटी पर इस 3 साल के कार्यकाल को कसा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के हर तबके के लोगों ने उसका विश्लेषण किया है और लोकतंत्र में एक उत्तम प्रक्रिया है और मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए, जनता-जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय निकाल करके हमारे काम की गहराई से विवेचना की, कहीं सराहना हुई, कहीं समर्थन आया, कहीं कमियां निकाली गई, मैं इन सब बातों का बहुत महत्व समझता हूं।

उन्होंने कहा कि जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो भी जब उजागर होती हैं तो उससे भी सुधार करने का अवसर मिलता है। बात अच्छी हो, कम अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, उसमें से ही सीखना है और उसी के सहारे आगे बढ़ना है। रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र को बल देता है। एक जागरूक राष्ट्र के लिए, एक चैतन्य पूर्ण राष्ट्र के लिए, ये मंथन बहुत ही आवश्यक होता है।

श्री मोदी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह एक सामान्य नागरिक हूँ और एक सामान्य नागरिक के नाते अच्छी-बुरी हर चीज़ का प्रभाव मुझ पर भी वैसा ही होता है, जैसा किसी भी सामान्य नागरिक के मन पर होता है। 'मन की बात' कोई उसको एक तरफ़ा संवाद के रूप में देखता है। कुछ लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से टीका-टिप्पणी भी

करते हैं, लेकिन इतने लम्बे तजुर्बे के बाद मैं अनुभव करता हूं, मैंने जब, 'मन की बात' शुरू की तो मैंने भी सोचा नहीं था। 'मन की बात' इस कार्यक्रम ने, मुझे हिन्दुस्तान के हर परिवार का एक सदस्य बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैं परिवार के बीच में ही घर में बैठ करके घर की बातें करता हूं और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, जिन्होंने मुझे ये बातें लिख करके भी भेजी हैं और जैसा मैंने कहा कि एक सामान्य मानव के रूप में, मेरे मन में जो प्रभाव होता है। फिर दो दिन पूर्व राष्ट्रपति भवन में आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदया सबने 'मन की बात' की एक विश्लेषणात्मक पुस्तक का समारोह किया।

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नाते, सामान्य नागरिक के नाते, ये घटना मुझे बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। मैं राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, स्पीकर महोदया का आभारी हूं कि उन्होंने समय निकाल करके, इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोगों ने 'मन की बात' को ये अहमियत दी। एक प्रकार से अपने आप में 'मन की बात' को एक नया आयाम दे दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून अब दुनिया के लिये जाना-पहचाना दिन बन गया है। विश्व योग दिवस के रूप में पूरा विश्व इसे मनाता है। बहुत कम समय में 21 जून का ये विश्व योग दिवस हर कोने में फ़ैल चुका है, लोगों को जोड़ रहा है। एक तरफ़ विश्व में बिखराव की अनेक ताक़तें अपना विकृत चेहरा दिखा रही हैं, ऐसे समय में विश्व को भारत की एक बहुत बड़ी देन है। योग के द्वारा विश्व को एक सूत्र में हम जोड़ चुके हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जैसे योग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। आज जीवन-शैली के कारण, आपा-धापी के कारण, बढ़ती हुई ज़िम्मेवारियों के कारण, तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है और ये बात देखने में आई छोटी-छोटी आयु में भी, ये स्थिति पहुंच चुकी है। अनाप-शनाप दवाईयां लेते जाना और दिन गुज़ारते जाना, ऐसी घड़ी में तनाव-मुक्त जीवन जीने के लिए योग की भूमिका अहम है। ■

ढोला-सदिया : पूर्वोत्तर के लिए नई आशा का पुल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को असम में देश के सबसे लम्बे नदी पुल ढोला-सदिया का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस पुल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का सपना बताया। उन्होंने कहा कि अगर 2004 में अटल सरकार दोबारा से चुनकर आती, तो यह पुल 10 साल पहले ही बन जाता। श्री मोदी ने कहा कि बीच में सरकार बदल गई, काम ऐसे ही चलता रहा और लोगों का सपना डगमगाता रहा।

साथ ही श्री मोदी ने इस पुल का नाम असम के मशहूर लोकगायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका पूरी जिंदगी ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान करते रहे, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान के बारे में याद दिलाते रहने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल, भूपेन हजारिका सिर्फ बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्मकार भी थे। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के से लेकर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को स्थाई रूप देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इसलिए उनकी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश और आसाम जुड़ जाएंगे, 165 किमी की दूरी कम हो जाएगी।

ढोला-सदिया पुल से पूर्वोत्तर में विकास के नये रास्ते खुलेंगे। इस पुल के निर्माण से सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने का मौका मिलेगा। यह पुल ऊपरी आसाम के ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उन्होंने कहा कि सदिया के किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाला अदरक बेहद उच्च क्वॉलिटी का होता है। पुल बनने के बाद इन किसानों के लिए रास्ता खुल जाएगा और उनकी कमाई में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुल सिर्फ पैसे और समय नहीं बचाएगा, बल्कि इलाके में नई अर्थ क्रांति लेकर भी आएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग फेरी सर्विस से आवाजाही करते थे, अगर मौसम ठीक न रहा तो सर्विस बंद हो जाती है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र रुठ जाए तो भी सर्विस रुक जाती थी। अब प्राकृतिक प्रकोप से लोगों की गति में कोई कमी नहीं आएगी।

गौरतलब है कि 9.15 किलोमीटर लम्बे तीन लेन के इस पुल

का निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर किया गया है। यह पुल असम के ढोला को अरूणाचल के सादिया से जोड़ेगा। इस पुल के अस्तित्व में आने से इस क्षेत्र में संपर्क का एक लम्बा अंतर खत्म हो जायेगा। अभी तक ब्रह्मपुत्र को पार करने के लिए केवल दिन के समय नौका का ही उपयोग किया जाता था और बाढ़ के दौरान यह भी संभव नहीं होता था। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना अंतिम पुल तेजपुर स्थित कालिया-भोमोरा पुल था। कल इस पुल का उद्घाटन होने के बाद ऊपरी असम और अरूणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के लिए 24X7 संपर्क सुनिश्ति हो जायेगा।

इस पुल के बनने से असम के राष्ट्रीय राजमार्ग–37 में रूपाई और अरूणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 में मेका/रोईंग के बीच 165 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। इन दो स्थानों के बीच यात्रा करने में वर्तमान में 6 घंटे का समय लगता है, जो अब घटकर 1 घंटा हो जायेगा और इस तरह 5 घंटे के समय की बचत होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल में 10 लाख रूपये तक की बचत होगी।

ढोला-सदिया पुल से पूर्वोत्तर में विकास के नये रास्ते खुलेंगे। इस पुल के निर्माण से सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने का मौका मिलेगा। यह पुल ऊपरी आसाम के ब्रह्मपुत्र और अरूणाचल प्रदेश के संपूर्ण आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा यह अरूणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा तथा राज्य में चल रही कई पणबिजली परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि संपर्क नहीं हो पाने के कारण कई बिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही थीं।

ढोला-सदिया पुल परियोजना की कुल लम्बाई दोनों तरफ की सड़कों को मिलाकर कुल 28.50 किलोमीटर है और पुल की लम्बाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण बीओटी एन्यूटी द्वारा किया गया, जिसकी कुल लागत 2,056 करोड़ रूपये है। इस पुल का उद्देश्य असम और अरूणाचल प्रदेश के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। ■

किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीन वर्ष में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो सतत प्रयास किए गये हैं, उनके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए जिस मनोयोग से काम में जुटी है, इससे किसानों के जीवन में गुणात्मक सुधार आ रहा है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य दिया है, जिसे हासिल करने के लिए कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। श्री सिंह ने ये बात 22 मई को मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए इन तीन वर्षों में देश के सामने नई कार्य-विधि, पारदर्शी कार्यशैली के नए प्रतिमान रचे हैं। सरकार ने समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में किसान कल्याण की योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है। सुशासन के नये आयामों, नवाचारों एवं सुधारवादी दृष्टिकोण से एक आधुनिक और भविष्योन्मुख भारत की नींव हमारी सरकार ने रखी है।

श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के मन में देश की कृषि उन्नति के लिए की गई नई पहलों के प्रति जागरूकता लाने में सफल हुई है। तीन वर्ष के कार्यकाल में किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का सतत् एवं सशक्त प्रयास किया है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला खर्च अधिकतर बजटीय प्रावधानों से कम रहता था। उदाहरण के लिए वर्ष 2011-12 में बजटीय प्रावधान रु 24,526 करोड़ था, जबकि खर्च मात्र रु 23,290 करोड़ रहा। इसी तरह 2012-13 में बजटीय में 28,284 करोड़ था, जबकि खर्च मात्र 24,630 करोड़ हुआ। वर्ष 2013-14 में बजटीय प्रावधान रु. 30,224 करोड़ था, जबकि खर्च रु. 25,896 करोड़ हुआ। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में किसान हित में मंत्रालय द्वारा खर्च बजटीय प्रावधान से ज्यादा किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप 2016-17 में जहां बजटीय प्रावधान रु 45035 करोड़ था, वह संशोधित बजटीय आवंटन में यह बढ़कर रु 57503 करोड़ किया गया है। मोदी सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक बजटीय आवंटन किया है। उदाहरणस्वरूप यूपीए सरकार के चार वर्ष यथा 2010-11 से 2013-14 के बजट में कुल

रु 1,04,337 करोड़ का बजटीय प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा 2014-15 से 2017-18 तक कृषि क्षेत्र को कुल 1,64,415 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं जो कि 57.58 प्रतिशत अधिक है।

श्री राधा मोहन सिंह ने आगे कहा कि विगत तीन वर्षों के प्रारम्भिक दो वर्षों में कम मानसून में भी किसानों को सुरक्षा एवं विश्वास का संबल सरकार द्वारा दिया गया है। स्वॉयल हैल्थ कार्ड का वितरण, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, कम लागत की जैविक खेती, राष्ट्रीय कृषि बाजार, बागवानी विकास, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, दुग्ध, मछली एवं अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार पर विशेष बल दिया गया है। सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी ज्यादा निवेश किया गया है।

दलहन-तिलहन में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कई नई पहलें तीन वर्षों में प्रारम्भ की गयी हैं। सबसे कम प्रीमियम एवं विभिन्न जोखिमों को शामिल कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजना (Contingency Plan) उपलब्ध कराए गए तथा सूखा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलने वाली राहत मानकों को बढ़ाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है।

श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में उन्नति एवं किसान कल्याण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा किसान सशक्तिकरण के लिए सतत् पहल एवं प्रयास के परिणाम दिखने लगे हैं।

मोदी सरकार की कृषि में उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन के पिछले सारे रिकार्ड टूट गये हैं। इस वर्ष कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 4.4 प्रतिशत रही है।
- 2016-17 के दौरान तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 273.38 मीलियन टन अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 की तुलना में 8.67% अधिक है।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न का यह उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से भी 6.37% अधिक है।
- 2016-17 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 22.40 मिलियन टन अनुमानित है जो अब तक का रिकार्ड उत्पादन होगा जो पिछले वर्ष 2015-16 से 37% अधिक है।
- 16.05.2017 तक 725 लाख स्वॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। नमूनों की जांच हो रही है। कार्ड छपाई का काम चल रहा है। आगामी तीन महीनों में शेष बचे किसानों का कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- वर्ष 2011-14 के दौरान जैविक खेती के तहत संचयी क्षेत्र 7.23 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2014-17 के दौरान 20 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- अब तक राष्ट्रीय कृषि बाजार से 417 मंडियां जुड़ चुकी हैं।
- 15.05.2017 तक 20,000 करोड़ रुपये के 84 लाख टन कृषि उत्पाद का कारोबार e-NAM पर हो चुका है। 15.05.2017 तक 46 लाख किसानों, 90 हजार व्यापारियों और 46,411 कमीशन एजेंटों को e-NAM प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया जा चुका है।
- दूध का उत्पादन 2011-14 के दौरान 398.01 मिलियन टन हुआ था, जो कि 2014-17 के दौरान बढ़कर 465.5 मिलियन टन हो गया है। तीन वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 16.9% रही है।
- वर्ष 2011-14 के दौरान अंडा उत्पादन 210.93 बिलियन था जो कि 2014-17 में बढ़कर 248.73 बिलियन हो गया। तीन वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 17.92 % रही है।
- वर्ष 2011-14 के दौरान मछली का उत्पादन 272.88 लाख टन था, जो कि 2014-17 के दौरान बढ़कर 327.74 लाख टन हो गया है। तीन वर्षों के उत्पादन विकास की वृद्धि दर 20.1% रही है।
- वर्ष 2011-14 तक 223 किसान उत्पादक संगठन बने, जबकि 2014-17 तक 383 बनाये गये।
- वर्ष 2007-14 तक 6.7 लाख ज्वॉइंट लाइबिलीटी ग्रुप बनाकर 7 वर्ष में 6630 करोड़ राशि दी गई जबकि 2014-17 तीन वर्षों में 15.85 लाख समूह बनाकर 16,268 करोड़ की राशि दी गई।
- मधुमक्खी पालन में 2011-14 तक 5.94 करोड़ खर्च किए गये, जबकि 2014-17 तक 18.14 करोड़ खर्च किए गये। 205 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- यू.पी.ए. के पांच वर्षों में राज्यों को राज्य आपदा अनुक्रिया कोष में 33,580 करोड रूपये स्वीकृत किए गये हैं। मोदी सरकार ने 5 वर्षों के लिए 61,260 करोड़ रूपये आवंटित किए है।
- यू.पी.ए. सरकार के 2011-12 से 2013-14 के तीन साल के बीच राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष में राज्यों को 9,099 करोड़ रूपये दिए गये। मोदी सरकार ने 2014-15 से 2016-17 के तीन वर्षों में राज्यों को 29,194 करोड़ दिये गये हैं, जबकि अभी इसके अलावा कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी विचाराधीन है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 8 लाख 40 हजार हेक्टेयर का रिकार्ड कवरेज सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत सिर्फ खरीफ सीजन में 2011-14 के तीन साल में 6 करोड़ किसानों ने बीमा कराया, जिसमें 77 लाख गैर ऋणी किसान थे। जबकि 2014-17 के बीच 3 वर्ष में सिर्फ खरीफ सीजन में 9 करोड 47 लाख किसानों ने बीमा कराया जिसमें 2 करोड 61 लाख गैर ऋणी किसान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आकर्षण के कारण खरीफ फसल में गैर ऋणी किसानों की संख्या में 238.96% की वृद्धि हुई है तथा इसी तीन वर्ष में इसके पूर्व के तीन वर्षों की तुलना में रबी फसलों में भी गैर ऋणी किसानों की संख्या में 128.50% की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की मुश्तैदी, राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग एवं किसानों की कड़ी मेहनत के बल पर कृषि क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विगत वर्षों में न सिर्फ सामना किया है, बल्कि विजय भी प्राप्त करते हुए सकारात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने आखिर में कहा कि प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की मुश्तैदी, राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग एवं किसानों की कड़ी मेहनत के बल पर कृषि क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विगत वर्षों में न सिर्फ सामना किया है, बल्कि विजय भी प्राप्त करते हुए सकारात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। ■

2013-2014 की तुलना में 2016-2017 में 5 गुना गांवों का बिजलीकरण

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति की सेवा) दर्शन के अनुरूप 20 नवबंर 2014 को भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को स्वीकृति दी। यह एकीकृत योजना है जिसमें ग्रामीण बिजली वितरण के सभी पक्ष यानी फीडर का अलगाव, प्रणाली सुदृढीकरण तथा मीटरिंग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंतत्रा दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1000 दिनों के अंदर बिजली से वंचित सभी गांव को बिजली प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया था। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रम को मिशन मोड में लिया और मई 2018 तक बिजलीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 15 मई 2017 तक बिजली सुविधा से वंचित 18,452 गांव में से 13,469 गांव में बिजली पहुंचा दी गयी है।

पूर्ववर्ती योजना के शेष ग्रामीण बिजलीकरण कार्य डीडीयूजीजेवाई में समाहित किये गये हैं। योजना की परिव्यय राशि 43,033 करोड़ रुपये है। इसमें 3345 करोड़ रुपये भारत सरकार का अनुदान है। पुराने ग्रामीण कार्य को समाहित करने के साथ समग्र परिव्यय राशि भारत सरकार की अनुदान राशि 63,027 करोड़ रुपये सहित 75,893 करोड़ रुपये है।

गौरतलब है कि नई डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) की दर से भारत सरकार अनुदान देती है। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 32 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 42,553.17 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। इनमें फीडर अलगाव के लिए (15572.99 करोड़ रुपये), प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण घरों से जोड़ने के लिए (19706.59 करोड़ रुपये), मीटरिंग (3874.48 करोड़ रुपये), ग्रामीण बिजलीकरण (2792.57 करोड़ रुपये) तथा सासंद आदर्श ग्राम योजना (398.54 करोड़ रुपये) शामिल है।

ग्रामीण बिजलीकरण कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए फील्ड में 350 से अधिक ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किये गये हैं। बिजली सुविधा से वंचित 18,452 गांवों में बिजलीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए जीएआरवी मोबाइल एप (garv.gov.in) विकसित किया गया। जीएआरवी एप में जीवीए फील्ड फोटोग्राफ, डाटा तथा अन्य सूचना अपडेट करते हैं। सभी 5.97 लाख गांवों में घरों के बिजलीकरण की निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2016 को अद्यतन जीएआरवी एप को लांच किया गया। अद्यतन जीएआरवी में संवाद-पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करने में नागरिकों को शामिल करना- का विशेष फीचर है।

योजना से ग्रामीणों की जीवन-शैली बदलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होने की आशा है। योजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हैं:

1. कृषि में उत्पादकता वृद्धि।
2. महिलाओं के लिए निरक्षरता कम करना।
3. बच्चों की शिक्षा में सुधार।
4. सभी गांवों तथा घरों से संपर्क।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली सेवा।
6. स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं देने में सुधार।
7. संचार साधनों (रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल) तक पहुंच में सुधार।
8. बिजली व्यवस्था से जन-सुरक्षा में सुधार।

योजना में राज्यों की स्थानीय आवश्यकता/प्राथमिकता के अनुसार कार्य चुनने में लचीलापन है। जनसंख्या मानक को समाप्त कर दिया है और जनसंख्या प्रतिबंध के बिना सभी गांवों/मोहल्लों को योजना के अंतर्गत पात्र माना गया है। डीपीआर तैयार करते समय राज्य जिला बिजली समिति (बीईसी) से परामर्श करेंगे और योजना में सांसदों के सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के प्रस्तावों को आवश्यक रूप से शामिल करना होगा। योजना की अन्य विशेषताओं में अनिवार्य ई-निविदा, मानक निविदा दस्तावेज का परिपालन शामिल है। निजी बिजली वितरण कंपनियां तथा आरई कोआपरेटिव सोसाइटी भी योजना के अंतर्गत पात्र हैं। योजना की समीक्षा दिशा (जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति) द्वारा की जा रही है। भारत सरकार ग्रामीण जनता की जिंदगी में परिवर्तन लाने और सभी के लिए 24X7 बिजली देने के लिए संकल्पबद्ध है। ■

ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल का शुभारंभ

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 16 मई को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ऑपरेशन क्लीन मनी का पोर्टल https://www.cleanmoney.gov.in आधिकारिक रूप से लांच किया।

9 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक बड़ी मात्रा में जमा की गई नकद राशि के ई-सत्यापन की शुरुआत के साथ 31 जनवरी, 2017 को आयकर विभाग द्वारा ऑपरेशन क्लीन मनी की तरफ कदम बढ़ाया गया। प्रथम चरण में ऐसे लगभग 18 लाख लोगों की पहचान की गई थी, जिनके मामले में नकद लेन-देन करदाताओं के प्रोफाइल से मेल नहीं खाते थे। ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया पर करदाताओं की अच्छी प्रतिक्रिया हासिल हुई और 9.72 लाख से भी ज्यादा करदाताओं ने 12 मई, 2017 तक अपने जवाब आयकर विभाग गये बगैर ही दे दिये। इन करदाताओं ने लगभग 2.89 लाख करोड़ रुपये की नकद जमा राशि से जुड़े 13.33 लाख खातों के लिए अपने जवाब पेश किये हैं। ऑनलाइन जवाब पर गौर किया गया है और संतोषजनक जानकारी मिलने पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल से एक ही स्थान पर व्यापक जानकारी सुलभ हो जायेगी, कर अनुपालन समाज सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सहभागिता संभव हो पायेगी और कर प्रशासन को पारदर्शी बनाना संभव हो पायेगा। ■

वस्तु और सेवा कर से सीमेंट, दवाईयां, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों सहित कई वस्तुओं पर कर बोझ कम होगा

सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और 125 रूपये पीएमटी तथा 14.5 प्रतिशत की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर कुल वर्तमान कर 29 प्रतिशत से अधिक है। अगर इसमें केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि शामिल करते हैं तो वर्तमान कुल कर 31 प्रतिशत से अधिक होगा। इसके विपरीत सीमेंट के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 28 प्रतिशत है।

आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायन संबंधी प्रणालियों सहित दवाईयों के मामले में भी कर का बोझ कम होगा। आम तौर पर दवाईयों पर छह प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। इनके अलावा दवाईयों पर सीएसटी, चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि भी लगते हैं। इन दरों पर वर्तमान कुल कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाईयों पर प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।

स्मार्ट फोन पर 2 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा दस्ता शुल्क -एनसीसीडी) लगता है। अलग अलग राज्यों में वैट दर 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होती है। स्मार्ट फोन पर भारित औसत वैट दर लगभग 12 प्रतिशत है। इस प्रकार स्मार्ट फोन पर कुल वर्तमान कर 13.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत स्मार्ट फोन के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।

इसी तरह सर्जिकल उपकरणों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर आमतौर पर 6 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। सीएसटी, चुंगी कर,प्रवेश कर आदि के साथ कुल वर्तमान कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत जीएसटी के तहत प्रस्तावित दर 12 प्रतिशत है। हवन सामग्री सहित पूजा सामग्री कर की किसी भी श्रेणी में नहीं होगी, हालांकि इनके सही कर निर्धारण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता					
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/- ☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/- ☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अमरकंटक, मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन का शुभारंभ और नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह पर ध्वज स्थापना और कलश पूजन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

तीन साल बेमिसाल

बड़े फैसले, कड़े फैसले

- कालेधन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक निर्णय
- सालों बाद बेनामी प्रॉपर्टी पर कड़ा कानून बना
- सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को मुँहतोड़ जवाब
- दशकों से लंबित OROP की माँग को पूरा किया
- सालों बाद GST पर सर्वसम्मति बनाई, देश को अब मिलेगी एक समान टैक्स व्यवस्था

खुशहाल परिवार सुविधाएं अपार

- 28 करोड़ गरीब बैंक से जुड़े
- मुद्रा योजना के तहत गरीबों को 7.5 करोड़ लोन दिये गए, कुल लोन राशि 3.15 लाख करोड़ है
- 2 करोड़ से भी अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन
- स्टेंट की कीमत में 80% तक की कटौती
- जन औषधि केन्द्र से दवाईयाँ सस्ती हुईं
- हर गरीब को पक्की छत देने का संकल्प

देश की तरक्की ईमानदारी पक्की

- 3 सालों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं
- कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम
- कोयला, स्पेक्ट्रम, एफ.एम. और पर्यावरण के मामलों में पूर्ण पारदर्शिता
- ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म

सबकी सुरक्षा सबका ख़्याल

- विदेशों में फँसे हज़ारों भारतीयों को सुरक्षित घर पहुँचाया गया
- पहली बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेन से करोड़ों लीटर पानी पहुँचाया गया
- दिव्यांगों को अवसरों के माध्यम से नया हौसला मिला
- आदिवासियों को अपनी ज़मीन का हक़ मिल रहा है

जन-जन का साथ बढ़ता विश्वास

- जन-भागीदारी से 'स्वच्छ भारत' एक जन आंदोलन बना
- 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ी
- कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को अप्रत्याशित साथ मिला और 2 करोड़ से अधिक लोगों ने 'भीम' ऐप डाउनलोड किया
- वी.आई.पी. कल्चर ख़त्म किया

देश-विदेश में बढ़ता मान भारत की नई पहचान

- भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था
- 'मेक इन इंडिया' को पूरे विश्व में पहचान मिल रही है
- पूरा विश्व उत्साह से योग दिवस मना रहा है
- अंतरिक्ष में भारत को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है

भारत का कल उज्ज्वल

- ग्रामीण सड़कों को अप्रत्याशित तेजी से बनाया जा रहा है
- भारतमाला और सेतु भारतम प्रोजेक्ट से देश का कोना-कोना जुड़ रहा है
- स्मार्ट सिटी से बेहतर कल का निर्माण हो रहा है
- देश-भर की पंचायतों को ब्रॉडबैंड से तेजी से जोड़ा जा रहा है
- जलमार्गों को भी ट्रांसपोर्ट के लिए विकसित किया जा रहा है
- रेल नेटवर्कों का विस्तार पहले से तेज हो रहा है और 6 नए शहरों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी

सशक्त नारी सशक्त भारत

- 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन
- मातृत्व अवकाश 12 हफ़्तों से बढ़ाकर 26 हफ़्ते
- गर्भावस्था में महिलाओं के पोषण के लिए 6000 रुपए की मदद
- मुद्रा लोन लाभार्थियों में 70% महिलाएं

नये भारत की शक्ति युवा शक्ति

- स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा
- 109 नये केन्द्रीय विद्यालय, 62 नवोदय विद्यालय, 7 नये आई.आई.एम., 6 नये आई.आई.टी. बनाए जा रहे हैं
- 1 करोड़ SC/ST/OBC छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति सीधी पहुँची
- स्टार्ट अप इंडिया के द्वारा युवाओं को नये अवसर

खेत खलिहान में आ रही नई जान

- मंडियों को सीधे किसानों से जोड़ा जा रहा है
- e-NAM से किसानों को फसल का सही दाम
- किसान को प्रचुर मात्रा में नीम-कोटेड यूरिया
- कम प्रीमियम पर किसानों को पूरा फसल बीमा
- इस साल किसानों द्वारा बंपर पैदावार

विकास का आधार नीतियों में सुधार

- पूरे देश में समान टैक्स व्यवस्था
- 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' में बड़ा सुधार
- इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून के माध्यम से बड़ा सुधार
- एफ.डी.आई. कानूनों में बड़ा उदारीकरण

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली
36 पृष्ठ कवर सहित
"रजिस्टर्ड"